



प्रधानमंत्री भाजपा प्रत्याशी के रूप में संसदीय क्षेत्र वाराणसी से नरेंद्र मोदी ने काशी कोटवार काल भैरव के दर्शन एवं मां गंगा को नमन उपरांत नामांकन पत्र दाखिल किया इस दौरान उनके सभी समर्थक उपस्थित रहे।

मुद्दा विहीन विपक्ष-भाजपा पर लोकतंत्र समाप्त करने का लगा रही आरोप: राजनाथ सिंह

बस्ती (जीकेबी)। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। ऐसे में वह भाजपा पर लोकतंत्र समाप्त करने का झूठा आरोप लगा रही है। भाजपा सरकार के लिए नहीं देश बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है, जबकि विपक्षी दल कुर्सी के लिए मैदान में हैं। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर कर भाजपा ने देश के उत्थान को गति दी है। केंद्रीय रक्षा मंत्री शनिवार को हरैया कस्बे के बीआरसी मैदान में लोकसभा प्रत्याशी हरीश द्विवेदी के समर्थन में चुनावी जन सभा को संबोधित कर रहे थे। कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय पटल पर देश की कमजोर छवि के लिए नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह की सरकारें जिम्मेदार रहीं। मोदी के नेतृत्व में भारत अब एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। आज भारत की आवाज को पूरी दुनिया गंभीरता से सुन रही है। राजनाथ सिंह ने भाजपा सरकार में हुए विकास कार्यों के साथ राम मंदिर निर्माण व अनुच्छेद 370 समाप्त करने के फैसलों का जिक्र करते हुए कहा कि हमने देशवासियों से किए गए वादों को पूरा किया। गरीबी दूर करने का काम भी भाजपा ने किया है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद प्रमाण मांगने वाले नेताओं पर कटाक्ष करते हुए कहा, ये वही लोग हैं जिन्हें राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है। राजनाथ सिंह ने पाक अधि कृत कश्मीर का जिक्र करते हुए कहा कि मैंने सेना के अधिकारियों के साथ हुई बातचीत में कहा था कि पीओके को भारत में शामिल करने के हमें आक्रमण नहीं करना पड़ेगा। वहां के लोग खुद को भारत में शामिल करने के लिए चलकर आयेंगे। आज पीओके लोग भारत में शामिल होने की स्वयं आवाज उठाने लगे हैं।



चुनाव में लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों पर होगी सख्त कार्रवाई

पडरौना (जीकेबी)। डीआईजी परिक्षेत्र गोरखपुर सुरेश राव ए कुलकर्णी ने लोकसभा चुनाव सकुशल संपन्न कराने को लेकर शुक्रवार को पुलिस अफसरों के साथ पुलिस लाइन के सभागार में समीक्षा बैठक की। उन्होंने शांति व्यवस्था के बीच निष्पक्ष ढंग से चुनाव कराने के लिए हुई तैयारियों के बारे में जानकारी लिया। उन्होंने कहा कि चुनाव में किसी तरह की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी और सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस लाइन के सभागार में डीआईजी जिले के सीओ, थानाध्यक्षों के साथ लोकसभा चुनाव सकुशल संपन्न कराने के लिए कानून व्यवस्था की जानकारी लेने के साथ अपराध की समीक्षा की। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण तथा निष्पक्ष ढंग से कराने के निर्देश दिया। इसके साथ ही आगाह किया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। निर्देश दिया कि चुनाव प्रक्रिया में किसी भी प्रकार से बाधा उत्पन्न करने वालों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करें। डीआईजी ने पुलिस अधिकारियों से उनके थाना क्षेत्र की स्थिति, अपराध की प्रवृत्ति, क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त की। जनपद की सीमा बिहार बॉर्डर से सटे होने के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं जैसे अवैध शराब और मादक पदार्थों की तस्करी आदि की रोकथाम के लिए संबंधित पुलिस अफसरों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बनाए रखने एवं पुलिस का व्यवहार जनता के प्रति अच्छा रखने के निर्देश दिया। जुआ, मिलावटी शराब और अन्य विषयों पर सख्त कार्रवाई करने के साथ ही लंबित विवेचनाओं का जल्द निस्तारण करने को कहा। क्षेत्र में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखने तथा निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पूरी तरह पालन करने का निर्देश दिया।

ओवरब्रिज के सुपरवाइजर को पीटा

कप्तानगंज (जीकेबी)। कस्बे के सुभाष नगर स्थित ओवरब्रिज निर्माण का कार्य देख रहे सीनियर सुपरवाइजर को शुक्रवार दोपहर कुछ लोगों ने पीट दिया। उन्होंने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। ओवरब्रिज निर्माण कार्य का सीनियर सुपरवाइजर धर्मेन्द्र कुमार फोटो ले रहे थे। उसी दौरान बोलेरो सवार आए लोगों ने उनकी पिटाई कर दी और भाग गए। एसओ राजकुमार बरवार ने बताया कि तहरीर मिली है। गाड़ी नंबर भी तहरीर में अंकित है। जांच पड़ताल की जा रही है।

ट्रक का ईंधन खत्म होने से लगा जाम

जीकेबी
पकवा इनार (कुशीनगर)। राष्ट्रीय राजमार्ग-28 पर निर्माणाधीन ओवरब्रिज के अंडरपास के निकट ईंधन खत्म होने से ट्रक खड़ा हो गया। इससे वाहनों का जाम लग गया। घंटों वाहन जाम में फंसे रहे। ट्रक में ईंधन भरवाने के बाद जाम से निजात मिली। जाम में फंसे यात्रियों व मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कुशीनगर में राष्ट्रीय राजमार्ग -28 पर ट्रकों में आने वाली खराबी चलते जेटी बावू तिराहे पर जाम लगता रहता है। शुक्रवार सुबह करीब नौ बजे एक ट्रक खराब हो गया। उसे मशक्कत से हटवाकर आवागमन आरंभ कराया गया। उसके बाद करीब सवा दस बजे गोरखपुर की तरफ से बिहार जा रहा ट्रक निर्माणाधीन ओवरब्रिज के अंडरपास के निकट ईंधन खत्म होने से बंद हो गया। ट्रक चालक ने ईंधन की व्यवस्था के लिए काफी प्रयास किया लेकिन, नाकाम रहा। सूचना पर पहुंची ट्रैफिक पुलिस ने कुछ समय तक रूट को डायवर्ट कर आवागमन चालू कराया। लेकिन, इससे व्यवस्था नहीं बनी, राजमार्ग पर वाहनों की कतार लंबी होती गई। इसकी सूचना पर एनएचआई के जिम्मेदार पहुंचे और ट्रक में ईंधन भरवाया। तब जाकर धीरे-धीरे वाहन आगे बढ़े। इस दौरान जाम में यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस संबंध में एनएचआई के पेट्रोलिंग इंचार्ज विश्राम सिंह ने बताया कि निर्माणाधीन ओवरब्रिज के नीचे एक ट्रक का ईंधन खत्म हो गया था। जिसके चलते राजमार्ग पर वाहनों की कतार लगी थी। सूचना मिलने पर ट्रक में ईंधन भरवाया गया। तब जाकर स्टार्ट हुआ और बिहार के लिए रवाना किया गया।

एटीएम कार्ड बदलकर उचक्के ने उड़ाए 40 हजार

पडरौना। अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र के गांव बैरिया बैरिया गांव निवासी सहीदुन निशा ने बताया कि 21 संदेह होने पर कार्ड की जांच की तो कार्ड बदला हुआ निवासी महिला के बैंक खाते से उचक्के ने 40 हजार अप्रैल को वह अपनी बेटी के साथ रुपये निक. मिला। एटीएम बूथ पर जाने के बाद वह युवक वहां से रुपये उड़ा दिए। महिला ने बताया कि वह अपनी बेटी लने एसबीआई के एटीएम बूथ पर गई थी। वहां पहले निकल चुका था। के साथ एटीएम से रुपये निकालने गई थी। रुपये से मौजूद एक युवक ने रुपये निकालने को लेकर उन्हें बैंक को जानकारी देकर कार्ड को तत्काल ब्लॉक करा निकालने के दौरान वहां मौजूद एक युवक ने भरोसे में ले लिया और पिन जानने के बाद उसने दिया गया। इस मामले में महिला की तहरीर पर पुलिस उसका एटीएम कार्ड लेकर बदल दिया और चार बार तकनीकी गड़बड़ी की बात बताकर कार्ड वापस कर ने अज्ञात के खिलाफ धोखाधड़ी व जालसाजी का केस में 10-10 हजार रुपये निकाल लिया। घटना 21 अप्रैल दिया। रुपये नहीं निकलने के बाद वह लौट रही थी दर्ज किया है। इस संबंध में सीओ कुंदन सिंह ने बताया की बताई जा रही है। महिला की तहरीर पर पुलिस ने कि इसी दौरान मोबाइल पर चार मैसेज आए, जिसमें कि तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर मामले की केस दर्ज कर लिया है। अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र के 40 हजार रुपये की निकासी करने की जानकारी हुई। छानबीन की जा रही है।

पारिवारिक विवाद और तनाव से

बढ़ रहा आत्महत्या का ग्राफ

संतकबीरनगर। जिले में आत्महत्या का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। आए दिन किसी न किसी कारण की वजह से लोग आत्महत्या कर रहे हैं। पिछले एक सप्ताह में चार लोगों ने मौत को गले लगा लिया। इसमें सबसे ज्यादा पारिवारिक विवाद और तनाव की वजह से मौत के मामले सामने आ रहे हैं। आत्महत्या के मामलों में हो रही लगातार बढ़ोतरी पुलिस का भी सिरदर्द बढ़ा रही है। तमाम लोग पारिवारिक विवाद व अन्य कारणों से मानसिक तनाव में आकर अवसाद ग्रस्त हो जाते हैं। हर तरफ से नाकामी दिखने पर आत्मघाती कदम उठा ले रहे हैं। उन्हें न तो अपने घर परिवार का ही ख्याल रह जाता है और न ही उनके पीछे परिवार के हालत की कोई चिंता रहती है। ऐसे में समाज से बेपरवाह लोग जहरीला पदार्थ खाकर अथवा फंदा लगाकर आत्मघाती कदम उठा ले रहे हैं। जिले में पिछले कुछ दिनों में आत्महत्या के मामलों की बढ़ोतरी हुई है।

फंदे से लटका मिला नवविवाहिता का शव, दहेज हत्या का आरोप

कुशीनगर। कसया थाना क्षेत्रन्तर्गत के मैनपुर पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। थोड़ी देर में कुशवाहा निवासी रजवाबर कोइरी टोला से हुई गांव के रजवाबर कुशवाहा टोला में पिछल्ले मायके वाले भी पहुंच गए और पुलिस को इसकी थी। ससुराल आने पर उसके पति, ससुर समेत शुक्रवार को नवविवाहिता का शव फंदे से लटका जानकारी दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। मिला। पुलिस ने शव को फंदे से उतरवाकर की जांच पड़ताल की। फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए। शव को फंदे कि उसके परिवार के लोग गाली दे रहे हैं और मायके वालों ने पुलिस को तहरीर देकर ससुराल से उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। शुक्रवार की वालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। मृतक दुर्गा देवी के भाई जितेंद्र कुशवाहा पुत्र सुबह सूचना मिली कि ससुराल वालों ने दुर्गा को ज्ञानवर्धक सूत्रानुसार, गांव निवासी सत्यनारायन नथुनी कुशवाहा निवासी पकहा उसरा टोला थाना मारकर उसका शव फंदे से लटका लटका दिया कुशवाहा की पांचवें नंबर की बहू दुर्गा देवी बघौचघाट जनपद देवरिया ने पुलिस को तहरीर है। सीओ कुंदन कुमार सिंह ने बताया कि पा. (23) पत्नी बबलू कुशवाहा का शुक्रवार की देकर ससुरालियों पर बहन की हत्या का आरोप स्टमार्टम रिपोर्ट से सही स्थिति का पता चलेगा। सुबह कमरे में छत के कुंडे से फंदे के सहारे लगाया। जितेंद्र ने बताया है कि फरवरी 2023 में दोषियों के विरुद्ध मुकदमा दर्जकर कार्रवाई की लटका शव मिला। इसकी जानकारी होते ही मौके दुर्गा की शादी बबलू कुशवाहा पुत्र सत्य नारायन जाएगी।

भाजपा नीत केंद्र सरकार का कार्यकाल जल्द ही समाप्त हो जाएगा

तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी ने शनिवार को संबोधित करते हुए बनर्जी ने भाजपा पर “गरीबों “केंद्र सरकार हर साल पश्चिम बंगाल से 1.20 लाख को दावा किया कि देश के मतदाता लोकसभा चुनाव के जीवन को दयनीय बनाने” का आरोप लगाया। करोड़ रुपये लेती है और राज्य को विभिन्न योजनाओं में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को सबक सिखाएंगे उन्होंने कहा, “भाजपा को एक सही सबक सिखाया के लिए केंद्र से 1.65 लाख करोड़ रुपये मिलना बाकी और केंद्र में भाजपा नीत राजग सरकार का कार्यकाल जाना चाहिए जो हमेशा खोखले वादे करती है। भाजपा है।” जल्द ही समाप्त हो जाएगा। ने 100 दिन के काम (मनरेगा) और आवास कार्यक्रम उन्होंने यह भी दावा किया कि हालांकि, केंद्र राज्य में जयनगर सीट से तृणमूल कांग्रेस जैसी विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के तहत पश्चिम बंगाल विभिन्न योजनाओं के तहत “भुगतान नहीं कर रहा उम्मीदवार प्रतिमा मंडल के समर्थन में पश्चिम बंगाल को भुगतान करना बंद कर दिया है।” तृणमूल कांग्रेस है” लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार गरीबों के लिए खुद के दक्षिण 24 परगना जिले के कुलतली में एक रैली प्रमुख ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कहा, इसका आर्थिक भार अपने खजाने से वहन कर रही है।



फ्लोरेंस नाइटेंगल की याद में आधीरात में भी लोग सुरक्षित महसूस करते हैं : स्वतंत्रदेव मनाया अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस



पडरौना (जीकेबी)। मेडिकल कॉलेज के सभागार में रविवार को फ्लोरेंस नाइटेंगल की याद में अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। नर्सों ने केक काटा और मोमबत्ती जलाकर फ्लोरेंस नाइटेंगल को याद किया।

कहा कि स्वास्थ्य सेवा को समाज में पहचान दिलाने वाली फ्लोरेंस नाइटेंगल की याद में नर्स दिवस मनाया जाता है। स्टाफ नर्स गीता, राजेश्वरी व संगीता ने कहा कि मेडिकल क्षेत्र में नर्सों की अहम भूमिका है। नर्सें मरीज की देखभाल करके उन्हें नया जीवन देती हैं। इसकी प्रेरणा फ्लोरेंस नाइटेंगल के जीवन से मिलती है। उन्होंने अपने जीवन में मरीजों की जो देखभाल की थी, वो शायद कोई नहीं कर सकता। इस दौरान बबीता, ममता, सुगंदा, नीतू, ज्योती, सुमन, राजमनी, अन्नया, कामिनी, विभा, मंजू, स्नेहा, मनोज, इंदू, मधू, राजमुनी आदि मौजूद रहीं।

स्वास्थ्य महानिदेशक ने महात्मा बुद्ध की प्रतिमा पर चढ़ाया चीवर

कुशीनगर(जीकेबी)। प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशक ने रविवार को कुशीनगर के प्रमुख दर्शनीय स्थलों का भ्रमण किया। उन्होंने महात्मा बुद्ध की प्रतिमा पर चीवर चढ़ाया। रविवार दोपहर करीब एक बजे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. बृजेश राठौर मुख्य महापरिनिर्वाण मंदिर पहुंचे। उन्होंने स्वर्ण आभायुक्त लेटी प्रतिमा की परिक्रमा कर चीवर चढ़ाया। प्रतिमा की तीन मुद्राओं व शोक संतप्त स्थिति में आगे की तरफ झुंकी स्त्रियों की विशेषताओं को भी जाना। यहां से भू-स्पर्श मुद्रा में मांथा कुंवर मंदिर में महात्मा बुद्ध की प्रतिमा के दर्शन किए। दोनों स्थलों पर परिसर में उत्खनित प्राचीन भग्नावशेषों की ऐतिहासिकता व प्राचीनता की भी जानकारी हासिल की। इसके अलावा थाई कला संस्कृति की अद्भुत नमूने में बने थाई मंदिर के कलाकृतियों व महात्मा बुद्ध की प्रतिमा के दर्शन किए। यहां भव्य चौत्य को भी देखा, जिसमें बुद्ध की पवित्र धातु अवशेष स्वर्ण कलश में बुलेटप्रूफ सुरक्षा के बीच संरक्षित है। यहां के बाद रामाभार स्तूप पहुंचे। जहां प्रवेश के दौरान पत्थर पर उत्कीर्ण स्थल की संक्षिप्त ऐतिहासिकता को पढ़ा। फिर आगे परिक्रमा कर वापस लौट गए। इस दौरान सीएमओ डॉ. सुरेश पटारिया, डॉ. संजय सिंह आदि मौजूद रहे।

अहिरोली बाजार (जीकेबी)। वर्ष 2014 के पहले देश में बम फूटते थे, लूट खसोट होती थी, महिलाएं सुरक्षित नहीं थीं, लेकिन अब बम नहीं फूटता है। कोई भूखे नहीं मरता है। 2017 के पहले प्रदेश में बेटियां घर से नहीं निकलती थी। पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार व गुंडागर्दी चरम पर थी, लेकिन आज आधी रात में भी लोग अपने आपको सुरक्षित महसूस करते हैं। प्रदेश से गुंडा माफियाओं का सफाया भाजपा सरकार ने किया है। अब जनता चैन की सांस ले रही है। प्रध नमंत्री नरेंद्र मोदी अगर तीसरी बार पांच साल मांग रहे हैं तो वह बीते दस सालों में किए गए काम के आधार पर मांग रहे हैं। हर घर नल, बिजली, राम मंदिर, धारा 370 हटाना, देशभर में हाईवे का जाल बिछाना, विश्वभर में भारत का मान बढ़ाने का काम पीएम मोदी ने ही किया है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, जहां मोदी के नेतृत्व में देश ने प्रगति न की हो।

ये बातें उत्तर प्रदेश सरकार के जलशक्ति एवं संसाधन मंत्री व भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शाम को घर पहुंचता है तो अपनी पत्नी की स्वतंत्रदेव सिंह ने कहीं। वे रविवार को हाटा क्षेत्र के सुभाष इंटर कॉलेज बेदूपार के परिसर में आयोजित भाजपा पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को बतौर मुख्य वक्ता संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 2014 के पहले की सरकारों में देश में धमाके होते थे। जब से मोदी सरकार बनी है, तब से धमाके बंद हो गए हैं। कांग्रेस ने 70 सालों से देश को लूटने का काम किया है। देश की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है। आज भाजपा सरकार



देश के लोगों के पास रहने के लिए पक्का मकान और इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड है। जनता से संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि पहले थका हारा किसान जब घर पहुंचता था तो रात के अंधेरे में चार रोटी के बदले दो रोटी ही खाता था। अब गांव में भी पर्याप्त बिजली रहने लगी है। जब किसान काम करने के बाद शाम को घर पहुंचता है तो अपनी पत्नी की शक्त उजाले में देखकर दो की बजाय आठ रोटी खाता है। स्वतंत्रदेव सिंह ने कहा कि भ्रष्टाचारी गठबंधन को जनता ने सिरे से नकार दिया है। भाजपा के परिश्रमी कार्यकर्ताओं की मेहनत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों तथा मजबूत नेतृत्व के दम पर हम चुनाव जीतेंगे और लगातार तीसरी बार सरकार बनाएंगे। राज्य सभा सांसद आरपीएन सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार में पिछड़े वर्ग को जितना

सम्मान मिला है, उतना किसी भी सरकार में नहीं मिला है। समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए आरपीएन सिंह ने कहा कि जिनको जनता ने रिटायर कर दिया है, वे तमाम तरह के भ्रम बनाकर पूरे कुशीनगर के लोगों को वह सम्मान दिया है, जिसे कुशीनगर में अबतक किसी को नहीं मिला था। सम्मेलन को पिछड़ा मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष चिरंजीवी चौरसिया, सांसद विजय कुमार दुबे, जिला प्रभारी शकुंतला चौहान, लोकसभा प्रभारी नरेंद्र मणि त्रिपाठी, विधायक प्रकाश गोंड, मोहन वर्मा, संजय सिंह मुन्ना, ब्लॉक प्रमुख अर्चना सिंह, रंजना पासवान, जिला मंत्री बाबूनंदन सिंह, पप्पू नाथानी ने भी संबोधित किया। अध्यक्षता पिछड़ा मोर्चा जिलाध्यक्ष जितेन्द्र सिंह ने की।

बुरे सपने से उबरना चाहती है कांग्रेस

दूसरे चरण के चुनाव के आसपास ही इंडिया ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के विदेशी सलाहकार अंकल सेम ने तीसरे दौर के चुनाव के पहले तब विरासत टैक्स का बम फोड़ दिया जब राहुल गांधी संपत्ति के पुनर्वितरण की बात कर रहे थे। मोदी को एनडीए के प्रचार के लिए यह बड़ा मुद्दा उन्होंने दे दिया। इन बयानों पर मोदी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। अभी संपत्ति के पुनर्वितरण और विरासत के टैक्स की गूंज शांत भी नहीं हुई थी कि पाकिस्तान के पूर्व सूचना प्रसारण मंत्री चौधरी फवाद का ऐसा एकतरफा बयान सामने आ गया जिसने मुसलमानों को भले ही खुश कर दिया होगा कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करने के लिए कांग्रेस के राहुल गांधी को वोट देना चाहिए लेकिन इसका समग्र जनता पर विपरीत असर होना तय है। इस पाकिस्तान के फवादी समर्थन ने कांग्रेस की मुसीबत और बढ़ा दी। यही नहीं, फरुख़ाबाद में सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम ने अपने एक भाषण में मोदी सरकार को हटाने के लिए मुसलमानों से वोट जिहाद की अपील कर यह स्पष्ट कर दिया कि समूचा मोदी विरोधी तबका मुस्लिम वोटो को एकजुट करने के लिए इस तरह के बयान दे रहा है। लोग भूल गए कि इंडी एलाइंस ने तो अपने प्रचार में लोकतंत्र खतरे में है, संविधान को बचाना है, जाति जन-गणना करानी है जैसे लोक लुभावन नारों के साथ आगे बढ़ना शुरू किया था किंतु संपत्ति का पुनर्वितरण, विरासत टैक्स, मोदी को हटाने के लिए मुसलमानों से एकजुट हो कर वोटकरने का फवाद चौधरी का आह्वान और वोट जिहाद वाले बयानों ने एक बार फिर दौड़ती कांग्रेस का पांव पकड़ लिया। यही नहीं, कांग्रेस कहती है कि यदि सत्ता में आई तो धारा 370 और तीन तलाक बहाल करेंगे जैसी घोषणा ने भी उसे हानि पहुंचाई है। हाल ही में महाराष्ट्र विधान सभा में विपक्ष के नेता विजय बड्टीवार ने 26/11 आतंकी हमले में मारे गए हेमंत करकरे की हत्या का आरोप कसाब की जगह एक कथित आरएसएस समर्थक पुलिस वाले पर लगाकर कांग्रेस को, पीछे धकेल दिया। यही नहीं, अजमल कसाब को फांसी की सजा दिलाने वाले उत्तर मध्य मुंबई से भाजपा प्रत्याशी और सर्वप्रिय वकील उज्ज्वल निकम को वे गद्दार कहकर कांग्रेस का कितना भला, कर रहे हैं, समझ से परे है। निश्चित ही ऐसे बयानों जिनसे कांग्रेस को हानि हो रही है, के लिए कांग्रेस स्वयं जिम्मेदार है। वहीं नरेंद्र मोदी की अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय लोकप्रियता के कारण वह पिछड़ती जा रही है। आज विपक्ष में ऐसा कोई नेता नहीं जो मोदी के कद की बराबरी कर सके। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का मिथ्या प्रचार भी उसके गले की हड्डी बनता जा रहा है क्योंकि वह कह रही है कि भाजपा आई तो संविधान बदलकर रख देगी, आरक्षण समाप्त कर देगी, लोकतंत्र खतरे में है। इस तरह के प्रचार से जनता पर कोई बहुत असर होता दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि जनता मानती है कि विगत 10 सालों में मोदी ने संविधान के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया ।

शुरूआत में कांग्रेस ने भी कुछ ऐसी गलतियां की जिनकी वजह से उसे अपने कदम पीछे खींचने पड़े कांग्रेस को पूरी उम्मीद थी कि 2023 के विधानसभा चुनावों में जहां वह राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बचा लेगी वहीं वह मध्य प्रदेश में भी जीत का परचम लहराएगी। लेकिन हुआ इसके विपरीत। कांग्रेस ने न केवल राजस्थान और छत्तीसगढ़ गंवाया बल्कि मध्य प्रदेश में

पिछले दो चुनावों में कांग्रेस ने लोकसभा में जो गठजोड़ किया उनसे सकारात्मक परिणाम तो नहीं ही मिले बल्कि उसकी स्थिति दयनीय होती चली गई। यही कारण है कि 2024 में इंडी एलायंस के घटक दलों ने कांग्रेस को अलप जनाधार की पाटी मानते हुए वह महत्व नहीं दिया जो उसे यूपीए के 10 सालों में विपक्ष ने दिया था। आज कांग्रेस का सम्मान और रुतबा 2019 के बाद लगभग खत्म सा हो गया है। परिणाम यह हुआ कि विपक्ष के उसके सभी साथियों ने अपनी शर्तों पर हर क्षेत्र में दोगम दर्जे का व्यवहार किया।

आशा के अनुरूप कांग्रेस प्रदर्शन नहीं कर पाई। इस समग्र प्रदर्शन से विपक्षी खेमा न केवल निराश हुआ बल्कि उसे लगने लगा कि कांग्रेस दोबारा अपने पैरों पर खड़ी होकर कुछ अच्छा कर पाएगी संभव नहीं है। लेकिन विपक्ष को दक्षिण भारत में कर्नाटक और तेलंगाना की जीत पर कांग्रेस से अच्छी उम्मीद के कारण इंडी एलायंस में बना रहना मुनासिब लगा जिसकी वजह से उसने कांग्रेस से सीमित संबंधों के साथ आगे बढ़ना उचित समझा। लेकिन इससे सबसे बड़ा झटका कांग्रेस को यह लगा कि उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में उसे बड़ा भाई बनकर नहीं बल्कि छोटा भाई बनकर शेष विपक्षी दलों के नेताओं की शर्तों को मनाना पड़ा। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव कांग्रेस के लिए मुसीबत ही लेकर आए थे। इस चुनाव में उसके प्रदर्शन पर ग्रहण लगाने वाले मणि शंकर अय्यर थे जिन्होंने कांग्रेस की नैया डुबाने के सारे जतन किए थे। मोदी तब केवल गुजरात के मुख्यमंत्री थे और संसदीय राजनीति का तो ककहरा भी नहीं जानते थे। यह मोदी का सबसे कमजोर पक्ष था। लेकिन उन्होंने चाय वाला, 56 इंच की छाती, विकास का गुजरात मॉडल और पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में जो प्रचार किया उसने जनमानस को अपने जादुई औरों में कैद कर लिया। मोदी तब हर आम सभा में स्वयं को चाय वाला कहते और कांग्रेस की तुष्टिकरण की नीति पाकिस्तान के विरुद्ध कठोर कदम न उठाने की कांग्रेस की नीति, धारा 370 और पाक आयोजित आतंकवाद के मुद्दे उठाकर जनता को अपने पक्ष में करते चले जाते। तब मणि शंकर अय्यर ने अपने फिजूल के गहन गंभीर ज्ञान और विदेश सेवा के कथित अनुभव से चाय वाले को घेरना शुरू कर दिया।

उन्होंने कहा कि देश की जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि वह एक चाय वाले को प्रधानमंत्री बनाए। यदि मोदी कांग्रेस वकींग कमेटी की मीटिंग में चाय

बेचना चाहें तो उसकी व्यवस्था की जा सकती है। लेकिन देश किसी चाय वाले को प्रधानमंत्री नहीं बना सकता। और देखते ही देखते चाय वाला जनता के बीच इतना पापुलर हो गया कि उसके दम पर 282 सीटें जीतकर भाजपा ने न केवल स्पष्ट बहुमत पाया बल्कि एनडीए को 336 सीटें दिला कर मोदी, ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। जो भी हो, कांग्रेस के लिए यह एक बुरा सपना था जिससे वह उबारना चाहती थी। साल 2019 आया तो कांग्रेस को लगा कि अब कोई ताकत नहीं है कि कांग्रेस को सत्ता में आने से रोक ले क्योंकि भाजपा सरकार के खिलाफ एंटी इनकंबेंसी एक बड़ा कारण बनेगी। लेकिन कहते हैं कि जब अच्छा समय न हों तो बुरे अपशकुन होने लगते हैं । ऐसा ही कांग्रेस के साथ हुआ। यही नहीं, कांग्रेस ने जोर-शोर से प्रचार शुरू किया भी। उसे लग रहा था कि इस बार वह कुछ अच्छा करेंगी। किंतु पता नहीं किस सलाहकार के कहने पर राहुल गांधी अपनी आमसभा में मोदी पर राफेल खरीद की डील पर न केवल भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाने लगे बल्कि अपनी सभाओं में चौकीदार चोर है का नारा लगाने लगे । यही नहीं, वे सामने बैठी भीड़ से उसे दोहराने को कहते। ऐसा लगता कि राहुल गांधी, राजीव गांधी के बोफोर्स तोप दलाली में आरोपित होने की तरह ही मोदी को भी राफेल के झमेले में फंसाकर जनता को भ्रमित करने में सफल हो जाएंगे और 2019 में मोदी की हार हो जाएगी। लेकिन परिणामों ने कांग्रेस को धराशायी कर दिया। बस अंतर यह हुआ कि जहां 2014 में उसकी कुल 44 सीटें आई थी, 2019 में उसे मात्र 52 सीटों पर संतोष करना पड़ा।

यही नहीं, राहुल गांधी खुद अमेठी से चुनाव हार गए। 2014 के बाद दूसरी बार कांग्रेस का अस्तित्व संकट में आ गया। राजनीतिक दलों और नेताओं की विशेषता होती है कि वह लगातार हार के बाद भी अगले चुनावों में संघर्ष के लिए कमर कसते हैं लेकिन कांग्रेस की हताशा तब दिखने लगी जब उसके बड़े नेता नेतृत्व पर सवाल खड़े करने लगे। बिना सत्ता के दस साल गुजारने वाली कांग्रेस ने 2024 में न केवल चौकीदार चोर है जैसे जुमले से परहेज किया बल्कि भारत जोड़ो यात्रा भाग एक और भाग दो कर जन समर्थन पाने की कोशिश की। निश्चित ही इन यात्राओं का सकारात्मक असर दक्षिण भारत के विधान सभा के चुनावों में तो दिखाई दिया किंतु वह उत्तर भारत में बहुत असर नहीं डाल सकी। चुनावी राजनीति में कांग्रेस पिछले 10 सालों से पिछड़ती जा रही है और आज के हालात भी बता रहे हैं कि इंडी धन की सारी कवायद के बाद भी उसके चुनावी परिणामों के प्रदर्शन में इस बार भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। यह इसलिए माना जा रहा है कि पिछले दो चुनावों में कांग्रेस ने लोकसभा में जो गठजोड़ किया उनसे सकारात्मक परिणाम तो नहीं ही मिले बल्कि उसकी स्थिति दयनीय होती चली गई। यही कारण है कि 2024 में इंडी एलायंस के घटक दलों ने कांग्रेस को अलप जनाधार की पाटी मानते हुए वह महत्व नहीं दिया जो उसे यूपीए के 10 सालों में विपक्ष ने दिया था। आज कांग्रेस का सम्मान और रुतबा 2019 के बाद लगभग खत्म सा हो गया है। परिणाम यह हुआ कि विपक्ष के उसके सभी साथियों ने अपनी शर्तों पर हर क्षेत्र में दोगम दर्जे का व्यवहार किया। कई स्थानों पर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर सकती थी वहां विपक्ष के साथियों ने अपना हक जता दिया।

भाजपा के संविधान में प्रधानमंत्री की उम्र का बंधन नहीं

जब पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहते प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में नरेन्द्र मोदी चुनाव में उतरे थे तब उन्हें भले ही इस बात का अहसास न रहा हो कि उनकी उम्र भी 75 पार कर सकती है। सत्ता में आने पर उन्होंने उनमें से अधिकांश लोगों को, जिन्होंने गिरे दिनों में संघर्ष करके पार्टी को जिंदा रखा था और उसे आगे बढ़ाने का काम किया था, एक-एक करके किनारे लगा दिए। कई नेताओं को जब 2019 में टिकट देने का सवाल आया तो उनकी 75 साल की उम्र का हवाला देते हुए घर बैठा दिया गया लेकिन 2024 में हेमामालिनी सरीखे कई उम्मीदवार उत्तर प्रदेश में ही 75 की सीमा पार कर चुके हैं फिर भी वह चुनाव मैदान में शायद इसीलिए रखे गए होंगे क्योंकि यह नियम भले ही भाजपा के संविधान का हिस्सा न हो लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वयं एक नियम के रूप में लोगों को राजनीतिक सन्यास के लिए रखा था। इसका उल्लंघन स्वयं भाजपा उत्तर प्रदेश में ही कई प्रत्याशियों को चुनाव में उतारकर कर रही है। इससे यही लगता है सारे नियम कानून दूसरों के लिए तैयार किए जाते हैं जब अपना प्रश्न आता है। तो वहां अपवाद दृढ़ लिया जाता है। सम्भवतः अमित शाह की सफाई भी इसी की एक कड़ी है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी नेता अरविन्द केजरीवाल ने कहा है कि मोदी जी को 400 सीटें इसलिए चाहिए कि वह केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह को अपना उत्तराधिकारी और श्रधानमंत्री बना सकें क्योंकि प्रधानमंत्री 2025 के सितम्बर में 75 वर्ष के हो जायेंगे और तब वह अमित शाह को प्रधानमंत्री बना देंगे। यही नहीं उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी तंज कसते हुए कहा है कि लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद यदि भाजपा जीतती है तो योगी आदित्यनाथ को भी मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाकर उनकी भी राजनीति उसी तरह खत्म कर देगी जैसा कि आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, शिवराज सिंह एवं अन्य भाजपा नेताओं का राजनीतिक भविष्य नरेन्द्र मोदी ने खत्म कर दिया है। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा यदि इस बार सत्ता में आयी तो सभी विपक्षी नेताओं को जेल में डाल देगी। केजरीवाल के चुनावी भाषण पर गृहमंत्री अमित शाह ने सफाई देते हुए कहा है कि नरेन्द्र मोदी ही तीसरी बार प्रध

जहां तक लोकसभा चुनाव का प्रश्न है प्रधानमंत्री तो अपने साक्षात्कारों और भाषणों में बार-बार कह चुके हैं कि वह 2024 की नहीं 2047 के विकसित भारत के बारे में तैयारी कर रहे हैं।

मोदी युग आया है, 75 साल के नाम पर बहुत से बड़े-बड़े नेताओं को किनारे लगा दिया गया और उन्हें मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया जिनकी अब कहीं कोई राजनीति नजर नहीं आती है। यह सब हाशिए पर जा चुके हैं। उनका कोई राजनीतिक भविष्य मोदी ब्रांड भाजपा में नहीं रह गया है।

अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में चलने वाली राजग सरकार समय पूर्व चुनाव कराने के निर्णय के साथ ही शईडिया शाइनिंग्स का नारा दिया था। इस नारे के प्रचार के लिए एक अनुमान के अनुसार टीवी और अखबारों में विज्ञापनों के लिए 20 मिलियन डालर की धनराशि खर्च की गई थी। भाजपा को पूरा भरोसा था कि वह सत्ता में वापसी करने जा रही है और इंडिया शाइनिंग के बलबूते स्वयं अपना बहुमत लाने में सक्षम होगी। यही कारण था कि सरकार बनाते वक्त सहयोगियों को साथ रखने के लिए विवादित मुद्दों, वह चाहे कश्मीर की विशेष स्थिति के बारे में अनुच्छेद 370 का प्रश्न हो, अयोध्या में राममंदिर का या समान नागरिक संहिता का प्रश्न क्यों न हो, इन सभी प्रश्नों को भाजपा ने सरकार चलाने के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया था। उसके लिए उस समय अपने मुद्दे के बजाय सरकार चलाना प्रमुख मुद्दा था। लेकिन चुनाव के बाद जो परिणाम आये वह सब उल्टा-पुल्टा हो गया।

कांग्रेस सत्ता में आ गई और इंडिया शाइनिंग का नारा फुस्स हो गया। जहां तक राजनीति में सरकारी सेवा की भांति रिटायर होने की उम्र की बात है भारत की राजनीति में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। कांग्रेस लम्बे समय तक सत्ता में रही है इसलिए उसके लिए कोई समस्या नहीं रही क्योंकि लंबी पारी खेलते हुए नेताओं की उम्र को चुनाव से जोड़कर नहीं देखा गया लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों को स्थापित नहीं थी उन्हें नए चेहरे देना मजबूरी थी। धीरे-धीरे राजनीति में हार जीत को प्रभावित करने वाली स्थिति में हो गया जिसके कारण स्थापित पार्टियों को भी क्षेत्रीय पार्टियों को मुकाबला करने के लिए पुरानी उम्र के नेताओं की बजाय नए उम्र के नेताओं को मैदान में उतरना पड़ा। जहां तक लोकसभा चुनाव का प्रश्न है प्रधानमंत्री तो अपने साक्षात्कारों और भाषणों में बार-बार कह चुके हैं कि वह 2024 की नहीं 2047 के विकसित भारत के बारे में तैयारी कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के अधिसूचना के पूर्व ही उन्होंने नई सरकार के गठन और उसके 100 दिन के एजेंडे के बारे में अपने सहयोगियों के साथ बैठक करके उन्हें काम भी सौंप दिए जहां तक 400 सीटों के जीतने का सवाल है यह तो जनता के हाथ में है पहली बार 1984-85 के लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी को 415 सीटें मिली थी यहां तक कि आजादी के बाद चुनाव में भी यह स्थिति नहीं थी।

बार व बेंच अपने दायित्व का निर्वहन निष्ठा व ईमानदारी से करें: तेज प्रताप तिवारी

गोरखपुर (जीकेबी)। न्यायरूपी रथ को मुकाम तक पहुंचाने का दायित्व संयुक्त रूप से बार व बेंच दोनों का है। इनके संबंध में कोई विरोधाभास नहीं होना चाहिए । नवागत न्यायिक अधिकारियों का स्वागत और स्थानांतरित अधिकारियों की विदाई बार की एक अच्छी परंपरा है। यहां के बार एसोसिएशन पर मैं गर्व महसूस करता हूं। यह बातें जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने बार एसोसिएशन सभागार में अधि

वक्ताओं के बीच कहीं। जिला जज एसोसिएशन की तरफ से नवागत न्यायिक अधिकारियों के स्वागत समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अभाव व प्रभाव से मुक्त होकर अपने स्वभाव के अनुरूप कार्य करने से अधिकांश समस्याएं हल हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि बार एसोसिएशन की गौरवशाली परंपरा काफी समृद्ध है वह अधिकारियों को न्याय दिलाने में बार-बार पेंशन दोनों की है भूमिका होती है दोनों को अपने कर्तव्य बधाई दो का निष्ठा और ईमानदारी से पालन करना चाहिए। कार्यक्रम की शुरुआत नवादा सफर जिला जज चंद्रभान सिंह दीपा राय रविंद्र कुमार सिद्धार्थ सिंह स्वामी मोहम्मद अंसारी सुदेश कुमार लघुवाद न्यायाधीश विनोद शर्मा अपर मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट ज्ञानेंद्र कुमार अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन सुषमा अकाउंट्स सिविल जज जूनियर डिवीजन थे सत्याग्रह एवं दीपिका को माला पहनकर स्वागत करने के साथ हुई। समारोह के वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक नारायण धर दुबे सुभाष शुक्ला के लीगल एंड डिफेंस काउंसिल. संजय पाटिल त्रिपाठी अभिमन्यु पांडे धीरेंद्र द्विवेदी ने व्यापार संगठन सिविल कोर्ट के गौरवशाली परंपरा पर अपने विचार रखें कार्यक्रम क्या है अध्यक्षता संगठन के अध्यक्ष भानु प्रताप पांडे ने तथा संचालन मंत्री बृजेश मणि त्रिपाठी ने किया।

शहर में अधिक हैं हाइपरटेंशन के मरीज

गोरखपुर (जीकेबी)। वैसे तो यह कहा जाता है पुरुषों (18.2 की प्रतिशत) की तुलना में महिलाएं (16.1 कि युवावस्था मस्ती में बीत जाती है, लेकिन सर्वे रिपोर्ट बताती प्रतिशत) कम तनावग्रस्त है। यह रिपोर्ट यह भी बता रही है कि देश में हरियाणा के युवा सबसे अधिक (32.25 प्रतिशत) तन

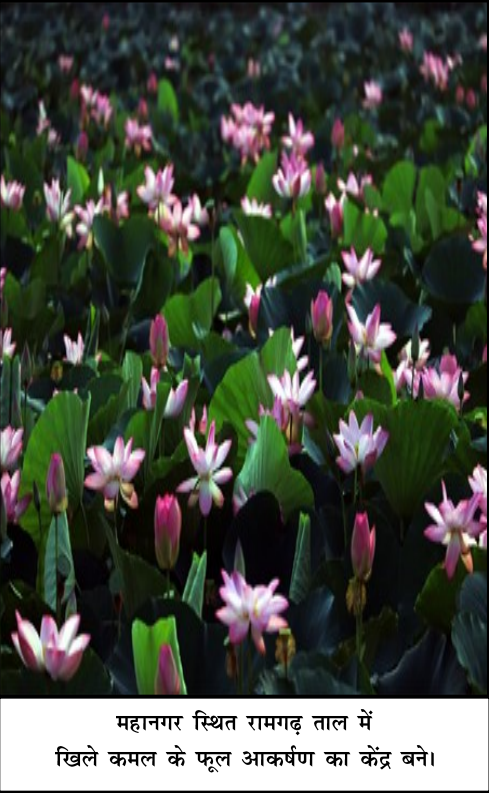
वैसा तो यह कहा जाता है पुरुषों (18.2 की प्रतिशत) की तुलना में महिलाएं (16.1 कि युवावस्था मस्ती में बीत जाती है, लेकिन सर्वे रिपोर्ट बताती प्रतिशत) कम तनावग्रस्त है। यह रिपोर्ट यह भी बता रही है कि देश में हरियाणा के युवा सबसे अधिक (32.25 प्रतिशत) तन। देश में 15 से 49 वर्ष के बीच के 17.2 प्रतिशत आबादी तनावग्रस्त हैं। हाइपर टेंशन की चपेट में है। इसमें से भी ग्रामीण आबादी (15.5 प्रतिशत) की तुलना में शहरी युवा (18.3 प्रतिशत) अधिक तनाव में हैं। इसकी बड़ी वजह अनियमित दिनचर्या के साथ ही गलत खानपान भी है। इसके अलावा स्वास्थ्य जागरूकता का अभाव भी एक बड़ा कारण है। एम्स के कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. यू वेंकटेश ने देश भर की व्यापक जरूरत है। पिछले वर्ष 39 से 40 डिग्री सेल्सियस के 803,211 लोगों के बीच हाइपर टेंशन पर एक सर्वे किया था। अध्ययन में 87 प्रतिशत महिलाएं और 13 प्रतिशत पुरुष थे। इनमें 39 से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहा, जबकि रात में भी 70 प्रतिशत ग्रामीण और 30 शहरी थे। सर्वे की रिपोर्ट बताती न्यूनतम तापमान भी 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना है कि देश के 17.2 प्रतिशत युवा हाइपर टेंशन के शिकार हैं। रहा। ऐसे में पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार तापमान अधिक इसमें शहरी (18.3 प्रतिशत) और ग्रामीण (15.5 प्रतिशत) है। रहने से गर्मी सता रही है।

तापमान में लगातार बढ़त का दौर जारी

गोरखपुर। तापमान में लगातार बढ़त का दौर जारी है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 42.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन का अब तक का सबसे अधिक है। मौसम विभाग में शनिवार से चिलचिलाती धूप के साथ गर्म हवा चलने का अनुमान जताया है। इसके चलते अब लोगों को लू के थपेड़े भी परेशान करेंगे। इधर 3-4 दिनों तक लगातार दिन के साथ रात का तापमान बढ़ने का भी आसार जताया गया है, जिसके चलते अब दिन के साथ रात में भी गर्मी परेशान करेगी। मौसम विभाग ने अनुकूल सिनाप्टिक परिस्थितियों एवं गर्म पछुआ हवाओं के रफ्तार बढ़ने से तीन से चार दिन तापमान में लगातार वृद्धि का अनुमान जताया है। इस दौरान प्रतिदिन एक से तीन डिग्री सेल्सियस का अनुमान जताते हुए अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का संभावना व्यक्त किया है। प्रदेश के पश्चिमी इलाके में गर्मी अपने चरम पर है। शुक्रवार को आगरा में अधिकतम तापमान 46.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो 50 साल में तीसरा सबसे गर्म दिन रहा। मौसम विशेषज्ञों की मानें तो इसका असर एक से दो दिन में गोरखपुर में भी देखने को मिल सकता है। 20 व 21 मई को दिन का तापमान 45 तक पहुंच सकता है। दिन के साथ ही न्यूनतम तापमान बढ़ने से रात भी अब गर्म होगी। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 42.4 व न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वातावरण में नमी भी घट कर शुक्रवार को 23 प्रतिशत रहा, जिसके चलते दिन में लोग गर्मी से परेशान दिखे। हालांकि धूप हल्की थी, लेकिन उमस ने बेचैन किए रखा। इससे पहले 29 अप्रैल को अधिकतम तापमान 42.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।

‘बार व बेंच अपने दायित्व का निर्वहन निष्ठा व ईमानदारी से करें’

गोरखपुर (जीकेबी)। न्यायरूपी रथ थे। उन्होंने कहा कि अभाव व प्रभाव से अपर मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट ज्ञानेंद्र कुमार को मुकाम तक पहुंचाने का दायित्व मुक्त होकर अपने स्वभाव के अनुरूप कार्य अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन सुषमा संयुक्त रूप से बार व बेंच दोनों का है। करने से अधिकांश समस्याएं हल हो जाती अकाउंट्स सिविल जज जूनियर डिवीजन थे सत्याग्रह एवं दीपिका को माला पहनकर चाहिए । नवागत न्यायिक अधिकारियों का उन्होंने कहा कि बार एसोसिएशन की स्वागत करने के साथ हुई। स्वागत और स्थानांतरित अधिकारियों की गौरवशाली परंपरा काफी समृद्ध है वह समारोह के वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक विदाई बार की एक अच्छी परंपरा है। यहां अधिकारियों को न्याय दिलाने में बार-बार नारायण धर दुबे सुभाष शुक्ला के के बार एसोसिएशन पर मैं गर्व महसूस पेंशन दोनों की है भूमिका होती है दोनों लीगल एंड डिफेंस काउंसिल संजय पाटिल करता हूं। यह बातें जनपद न्यायाधीश तेज को अपने कर्तव्य बधाई दो का निष्ठा और त्रिपाठी अभिमन्यु पांडे धीरेंद्र द्विवेदी ने प्रताप तिवारी ने बार एसोसिएशन सभागार ईमानदारी से पालन करना चाहिए। व्यापार संगठन सिविल कोर्ट के गौरवशाली में अधिवक्ताओं के बीच कहीं। जिला कार्यक्रम की शुरुआत नवादा सफर जिला परंपरा पर अपने विचार रखें कार्यक्रम क्या जज एसोसिएशन की तरफ से नवागत जज चंद्रभान सिंह दीपा राय रविंद्र कुमार है अध्यक्षता संगठन के अध्यक्ष भानु प्रताप न्यायिक अधिकारियों के स्वागत समारोह सिद्धार्थ सिंह स्वामी मोहम्मद अंसारी सुदेश पांडे ने तथा संचालन मंत्री बृजेश मणि को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे कुमार लघुवाद न्यायाधीश विनोद शर्मा त्रिपाठी ने किया



महानगर स्थित रामगढ़ ताल में खिले कमल के फूल आकर्षण का केंद्र बने।

जाति सूचक शब्दों से बचें, लग सकता है एससी एसटी का केस

प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति के विरुद्ध अनजाने में की गई जातिसूचक टिप्पणी पर एस सी-एसरटी एक्ट की धारा 3(2) (बी) का अपराध नहीं बनता। ऐसा अपराध तभी माना जाएगी जब टिप्पणी करने वाला जानता हो कि, जिसके खिलाफ जातिसूचक अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा है वह अनुसूचित जाति का व्यक्ति है।

न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की कोर्ट ने देहरादून निवासी एक याची के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए सहारनपुर ऐसे ही मामले की पूरी केस कार्यवाही रद कर दी। प्रकरण 18 अगस्त, 2023 का है। देहरादून निवासी लका सेठी का कहना था कि उसने लोकेश मित्तल से सहारनपुर में जमीन का बैनामा कराया था। दाखिल-खारिज कराने के बाद सीमांकन की मांग की। इसमें देरी की जा रही थी। याची का आरोप है कि भू-माफिया, राजस्व अधिकारियों व तत्कालीन एसएचओ की मिलीभगत से बैनामे से खरीदी उसकी जमीन की पैमाइश कराने के लिए उसे आफिस के चक्कर लगाने को मजबूर किया गया।



पीओके हाथ से निकल जाने के डर से सहमा पाकिस्तान

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में पाकिस्तान सरकार की तानाशाही, उदासीनता, उपेक्षा एवं दोगली नीतियों के कारण हालात बेकाबू, अराजक एवं हिंसक हो गये हैं। जीवन निर्वाह की जरूरतों को पूरा न कर पाने से जनता में भारी आक्रोश एवं सरकार के खिलाफ नाराजगी चरम सीमा पर पहुँच गयी है। गेहूँ के आटे और बिजली की ऊँची कीमतों के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन चल रहा है। प्रदर्शनकारियों एवं सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पों में एक पुलिस अधिकारी की मौत हो गयी जबकि 100 से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों में अधिकतर पुलिसकर्मी हैं। पीओके के लोग पाकिस्तान सरकार की नाकामी के खिलाफ सड़कों पर हैं। पाकिस्तान को पीओके के हाथ से निकल जाने का डर सताने लगा था। पीओके की आवाज दबाने के लिए पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया है एवं आन्दोलनकारियों को दबाने की दमनकारी कोशिशें की जा रही है। पीओके के बगावती तेवर देख पाकिस्तान के हाथ-पांव फूल गये हैं। दरअसल, अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान के कब्जे के बाद से ही पीओके लगातार सरकार की उपेक्षा, उत्पीड़न एवं उदासीनता झेल रहा है। उसकी समस्याओं और विकास पर ध्यान देने की बजाय पाकिस्तान का जोर वहां आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप खोलने पर ज्यादा रहा। पाकिस्तान की सरकार ने पीओके का इस्तेमाल भारत में अशांति, आतंक एवं हिंसा फैलाने के लिये किया है, वह पीओके के माध्यम से कश्मीर को हड़पने की हर संभव कोशिश करता रहा है, लेकिन वहां के निवासियों की जरूरतों पर कभी ध्यान नहीं किया। यूं तो अभी समूचे पाकिस्तान के हालात बद से बदतर हैं, गरीबी, महंगाई एवं आर्थिक दिवालियापन से घि रा है, दुनियाभर से आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिये झोली लिये घूम रहा पाकिस्तान भारत में अशांति एवं आतंक फैलाने से बाज नहीं आ रहा है। दरअसल, पाकिस्तानी कमरतोड़ महंगाई एवं जनसुविधाओं से जूझ रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 3 अरब डॉलर के कर्ज की मंजूरी देते समय कड़ी शर्तों लगाई थीं, जिसके कारण स्थिति और खराब हो गई है। बिजली दरों में बढ़ोतरी से दिक्कतें बढ़ गई हैं और पाकिस्तान में लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए हैं। इन्हीं जर्जर एवं जटिल हालातों के बीच पीओके के हालात पाकिस्तान के लिये पीओके को पाकिस्तान से मुक्त कराकर भारत में शामिल नया सिर दर्द बन गया है। पाकिस्तान के सुरक्षा बल करना पहले से निश्चित है। पीओके का ताजा संघर्ष एवं



प्रदर्शनकारियों के मुजफराबाद मार्च को दबाने की जितनी कोशिश कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन उतना ही उग्र हो रहा है। पीओके की अवामी एक्शन कमेटी के मार्च और धरने के आह्वान के बाद बेकाबू होते हालात 1955 के अवज्ञा आंदोलन की यादें ताजा कर रहे हैं, जब पीओके के लोगों और पाकिस्तानी फौज में सीधा टकराव हुआ था। अब फिर पीओके के लोगों के उबलते गुस्से ने पाकिस्तानी हुकूमत के माथे पर बल बढ़ा दिए हैं, समस्या को अनियंत्रित एवं अनिश्चित हालात में पहुंचा दिया है। पीओके के सबसे उत्तरी इलाके गिलगित बाल्टिस्तान के लोग पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ मिलाए जाने की मांग कर रहे हैं। पीओके में आजादी के नारे लगने एवं उसे लद्दाख के साथ मिलाए जाने की मांग के बाद शहबाज शरीफ सरकार और पाकिस्तानी सेना दोनों सकते में है। पाकिस्तान के अत्याचार के खिलाफ पीओकी की जनता जिस तरह खड़ी हो गई, उसने पाकिस्तानी नीति निर्माताओं को तनाव में ला दिया है। हजारों की संख्या में कश्मीरी लोग पीओके में जगह-जगह सड़कों पर उतर आए तो पाकिस्तान को पीओके के हाथ से निकल जाने का डर सताने लगा है। पीओके में विरोध को दबाने के लिए पाकिस्तानी दमन चक्र शुरू हो गया है। इसमें पाकिस्तान रेंजर्स और फ्रंटियर कोर को भी लगाया गया है। पीओके के सभी 10 जिलों में इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद कर दी गई हैं। भाजपा की मोदी सरकार के मुख्य एजेंडे में पीओके को पाकिस्तान से मुक्त कराकर भारत में शामिल करना पहले से निश्चित है। पीओके का ताजा संघर्ष एवं

आन्दोलन भाजपा की राह को निश्चित ही आसान करेंगी। भारत के विभाजन के तुरंत बाद पाकिस्तान द्वारा जम्मू और कश्मीर की रियासत पर आक्रमण करने के बाद पीओके बनाया गया था। पाकिस्तानी सेना और आदिवासी हमलावरों के हमले के तहत, महाराजा हरिसिंह ने भारत से सैन्य मदद मांगी, जिसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को पूरी रियासत पर कब्जा करने से रोक दिया। अब, लगभग सात-आठ दशक से अधिक समय के बाद, जबकि पाकिस्तान भारी वित्तीय, राजनीतिक और मानवीय संकट में फंस गया है, जबकि भारत अपने आर्थिक, राजनैतिक और वैज्ञानिक मापदंडों में तेजी से आगे बढ़ रहा है और अपनी सैन्य शक्ति को सशक्त कर रहा है। जम्मू-कश्मीर में विकास की गंगा बह रही है, वहां के लोग शांति, शिक्षा, व्यापार एवं विकास की दृष्टि से नये कीर्तिमान गढ़ रहे हैं जबकि पीओके कम मानव विकास के साथ आर्थिक प्रगति से वंचित जनजीवन से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहा है। स्वयं को ठगा महसूस करते हुए पीओके की आम जनता अब शांति चाहती है, अमन चाहती है, विकास चाहती है, जोकि पाकिस्तान में रहते हुए असंभव है। दोगली नीतियों के चलते पीओके के प्राकृतिक संसाधनों का पाकिस्तान खुलकर दोहन करता रहा, जबकि वहां के लोग ईंधन, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा और जरूरी बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझते रहे। पीओके के लोगों ने मई 2023 में बिजली की ऊंची दरों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था, जो एक साल बाद अब उग्र रूप ले चुका है। आंदोलन से काफी पहले पीओके के लोगों का भारत के प्रति झुकाव समय-समय पर मुखर होता रहा है। पाकिस्तान

की राजनीति की दूषित हवाओं ने पीओके की चेतना एवं सोच को आन्दोलनकारी बना दिया है। सत्ता के गलियारों में स्वार्थों की धमाचौकड़ी देखकर वहां के लोग समझ गये कि उनका शोषण एवं उत्पीड़न ही हो रहा है। यही कारण है कि पिछले साल पीओके और गिलगित के लोगों ने पाकिस्तान की भेदभाव वाली नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान अपने इलाकों को भारत के साथ मिलाने को ही अपने हित एवं शांतिपूर्ण जीवन के अनुरूप मानने लगे हैं। इसके लिये किये गये तब के प्रदर्शन के सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में वहां के लोग ‘आर-पार जोड़ दो, करगिल को खोल दो’ जैसे नारे लगाते नजर आए थे। वहीं, देश भर में गेहूँ के आटे की कमी, बलूचिस्तान में उग्रवाद, अफगानिस्तान के साथ सीमा संघर्ष, पाकिस्तानी तालिबान द्वारा हमलों और एक गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के साथ, पीओके में लोगों ने काफी कड़वे अनुभव किये हैं। निर्वासित पीओके नेता, शौकत अली कश्मीरी भी पीओके में लोगों के सामने आने वाली कठिनाइयों को उजागर करने के लिए दिसंबर से विभिन्न देशों में बैठकें कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में जिनेवा में समाचार एजेंसी एएनआई से कहा कि पाकिस्तान ने 1948 से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया है लेकिन बदले में पीओके में लोगों को बेरोजगारी और निर्वासन मिला। अधि कांश लोगों को चिकित्सा सुविधा नहीं होने के कारण बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। पीओके के लोग चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) का भी विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि गलियारे की आड़ में उनकी जमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए किया जाएगा और भारत के जवाबी हमले उन्हें झेलने पड़ेंगे। चूँकि भारत अब पहले वाला भारत नहीं रहा, उसकी सैन्य ताकत का मुकाबला करना पाकिस्तान के लिये संभव नहीं रहा है, इसलिये बिना मतलब भारत के आक्रमण को झेलने से स्वयं को बचाने के लिये पीओके के लोग भारत में विलय को ही उचित मानते हैं। पीओके में विरोध प्रदर्शन के दौरान जिस तरह भारतीय तिरंगा लहराया जा रहा है और भारत में विलय के स्वर उठ रहे हैं, उससे भविष्य में इस विवादित क्षेत्र पर निर्णायक पटकथा लिखे जाने के आसार नजर आ रहे हैं। भारत को पीओके के घटनाक्रम पर नजर बनाए रखने की जरूरत है, ताकि इससे हमारे सुरक्षा हितों पर प्रतिकूल असर न पड़े एवं भविष्य की नीतियों का निर्धारण करने में सुविधा रहे।

बिना स्वतंत्र मीडिया के स्वस्थ लोकतंत्र को सुनिश्चित कर पाना असंभव

राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते राजनेताओं और मीडिया घरानों के बीच सांठगांठ के परिणामस्वरूप अक्सर पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग होती है और असहमति की आवाजों का दमन होता है। धमकियाँ और हमले: पत्रकारों को शारीरिक हिंसा, उत्पीड़न और धमकी का सामना करना पड़ता है, खासकर जब वे भ्रष्टाचार, मानवाधिकार उल्लंघन या सांप्रदायिक तनाव जैसे संवेदनशील मुद्दों को कवर करते हैं। कभी-कभी पत्रकारों को चुप कराने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के लिए राजद्रोह, मानहानि और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जैसे कानूनों का दुरुपयोग किया जाता है। मीडिया संगठन, विशेष रूप से छोटे संगठन, वित्तीय बाधाओं का सामना करते हैं, जिसके कारण पत्रकारिता मानकों से समझौता होता है और कॉर्पोरेट या राजनीतिक फंडिंग पर निर्भरता होती है।



महात्मा गांधी का यह कथन कि “प्रेस की स्वतंत्रता एक अनमोल विशेषाधिकार है जिसे कोई भी देश त्याग नहीं सकता” आज के वैश्विक संदर्भ में दृढ़ता से प्रतिध्वनित होता है। भारत में, एक जीवंत और स्वतंत्र प्रेस न केवल संविधान में निहित एक मौलिक अधिकार है, बल्कि लोकतंत्र की आधारशिला भी है, जो एक प्रहरी, सूचना का प्रसारक और विविध आवाजों के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। हालाँकि, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की वर्तमान स्थिति विभिन्न चुनौतियों के कारण जांच के अधीन है। भारत में प्रेस स्वतंत्रता की वर्तमान स्थिति पर नजर डाले तो भारत में एक विविध मीडिया परिदृश्य है जिसमें प्रिंट, प्रसारण और डिजिटल प्लेटफॉर्म शामिल हैं। हालाँकि यहाँ काफी हद तक स्वतंत्रता है, फिर भी प्रेस की स्वतंत्रता और अखंडता के संबंध में चिंताएँ उठाई गई हैं। सेंसरशिप, स्व-सेंसरशिप, राजनीतिक हस्तक्षेप और पत्रकारों पर हमलों की घटनाओं ने प्रेस की स्वतंत्रता के क्षरण के बारे में चिंता बढ़ा दी है। राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते राजनेताओं और मीडिया घरानों के बीच सांठगांठ के परिणामस्वरूप अक्सर पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग होती है और असहमति की आवाजों का दमन होता है। धमकियाँ और हमले: पत्रकारों को शारीरिक हिंसा, उत्पीड़न और धमकी का सामना करना पड़ता है, खासकर जब वे भ्रष्टाचार, मानवाधिकार उल्लंघन या सांप्रदायिक तनाव जैसे संवेदनशील मुद्दों को कवर करते हैं। कभी-कभी पत्रकारों

को चुप कराने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के लिए राजद्रोह, मानहानि और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जैसे कानूनों का दुरुपयोग किया जाता है। मीडिया संगठन, विशेष रूप से छोटे संगठन, वित्तीय बाधाओं का सामना करते हैं, जिसके कारण पत्रकारिता मानकों से समझौता होता है और कॉर्पोरेट या राजनीतिक फंडिंग पर निर्भरता होती है। इंटरनेट ने मीडिया की पहुंच का विस्तार किया है, इसने गलत सूचना और फर्जी खबरों के प्रसार को भी बढ़ावा दिया है, जिससे पारंपरिक मीडिया आउटलेट्स की विश्वसनीयता कम हो गई है। यह बहुत शर्मनाक बात है कि हमारे जैसे लोकतांत्रिक देश में प्रेस की आजादी की स्थिति पर कोई खतरा मंडराये। इस स्थिति के लिए किसी एक व्यक्ति या एक संस्था को जिम्मेवार मानना बहुत गलत होगा। लेकिन, इसके साथ ही यह भी सत्य है कि यह हमारे लिए आत्मचिंतन का समय है। यह आत्मचिंतन सरकारों को करनी है, नेताओं को करनी है, पत्रकार बंधुओं को करनी है, रिपोर्टर्स को करनी है और खास तौर पर पत्रकारिता संस्थानों के मालिकों को करनी है, कि हम किस तरह की पत्रकारिता चाहते हैं। आज यह आत्मचिंतन का विषय है कि हम क्यों पत्रकार बने या आनेवाली पीढ़ियों में कोई क्यों पत्रकार बने। आज ये सवाल हमें अपने आप से पूछने हैं। साथ ही, किसी रैंकिंग आदि को देख कर यह समझना भी गलत है कि हम (प्रेस) बिल्कुल भी आजाद नहीं है। लेकिन, इतना

सच जरूर है कि मीडिया में- खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में-आजकल खबरें कम, एजेंडा ज्यादा चलाया जा रहा है। यहीं आकर सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं, क्योंकि खबरों को इकट्ठा करनेवालों पर संस्थान मालिकों का दबाव होता है। ज्यादातर तो मालिक ही संपादक होते हैं, जो एजेंडा चलाये जाने के जाल में फंस जाते हैं। दरअसल, एजेंडा चलाना आज के दौर में मीडिया का बिजनेस मॉडल है और यह मॉडल जब तक रहेगा, तब तक तो प्रेस पर सवाल उठते रहेंगे कि आखिर वह कितना आजाद है और उस पूंजी कितनी हावी है।यहां पर एक बात बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। वह यह कि मौजूदा दौर की वेब पत्रकारिता यानी डिजिटल मीडया इस बिजनेस मॉडल से थोड़ी अप्रभावित है, क्योंकि इसे चलाने में कम खर्च होने के चलते इस पर दबाव कम रहता है। प्रेस की स्वतंत्रता को कायम रखने के संभावित उपाय देखें तो कानूनी सुधार से उन कानूनों को संशोधित या निरस्त करें जिनका उपयोग प्रेस की स्वतंत्रता को कम करने के लिए किया जाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी के साथ संरेखित हों। पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए धमकियों या हमलों का सामना करने वाले पत्रकारों को पर्याप्त सुरक्षा और कानूनी सहायता प्रदान करना तथा अपराधियों को जवाबदेह ठहराना होगा।

मीडिया साक्षरता के माध्यम से प्रचार और गलत सूचना

से विश्वसनीय जानकारी को पहचानने के लिए जनता को शिक्षित करने के लिए मीडिया साक्षरता कार्यक्रमों को बढ़ावा देना होगा। नैतिक पत्रकारिता हेतु मीडिया संस्थानों को पेशेवर नैतिकता और मानकों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना, तथा ईमानदारी और जवाबदेही की संस्कृति को बढ़ावा देना और स्वतंत्र मीडिया के लिए बाहरी प्रभावों पर निर्भरता कम करने के लिए स्वतंत्र मीडिया संगठनों को वित्तीय सहायता और नियामक समर्थन प्रदान करना कारगर उपाय होगा। महात्मा गांधी द्वारा मान्यता प्राप्त स्वस्थ लोकतंत्र के कामकाज के लिए स्वतंत्र प्रेस का अधिकार आवश्यक है। जबकि भारत में एक जीवंत मीडिया परिदृश्य है, प्रेस की स्वतंत्रता के लिए चुनौतियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए सरकार, मीडिया संगठनों, नागरिक समाज और जनता के ठोस प्रयासों की आवश्यकता है। प्रेस की स्वतंत्रता को कायम रखकर, भारत अपने लोकतांत्रिक ताने-बाने को मजबूत कर सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि उसके नागरिकों की आवाज बिना किसी डर या पक्षपात के सुनी जाए।

-प्रियंका सौरभ



दैनिक जीवन को प्रभावित करती बालविवाह प्रथा

हमारे देश में प्राचीन समय से कुछ ऐसी प्रथाएं चली अपना बाल विवाह रुकवाने का प्रयास करने लगी है। आ रही है। जिसका लोगों के दैनिक जीवन पर बुरा प्रभाव भारत में यह प्रथा लम्बे समय से चली आ रही है जिसके पड़ता है। जिनमें बाल विवाह भी एक हैं। किसी भी बच्चे तहत छोटे बच्चों का विवाह कर दिया जाता है। आश्चर्य की शादी उसके निश्चित आयु से पहले यानी बाल्यकाल की बात तो यह है कि आज के पढ़े लिखे समाज में में होना बाल विवाह कहलाता है। यह एक रूढ़िवादी प्रथा भी यह प्रथा अपना स्थान बनाए हुए है। जो बच्चे है। यह प्रथा बच्चों की सारे मनवा अधिकारों को खत्म कर अभी खुद को भी अच्छे से नहीं समझते। जिन्हें जिन्दगी देता है। जैसे- खेलकूद, मनोरंजन, शिक्षा आदि के अधि की कड़वी सच्चाईयों का कोई ज्ञान नहीं। जिनकी उम्र कारों को समाप्त कर उन्हें ऐसे बंधन में बांध दिया जाता अभी पढ़ने लिखने की होती है। उन्हे बाल विवाह के बंधन है, जिसके बारे में उन्हें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता है। प्राचीन सभी प्रथाओं में बाल विवाह सबसे बड़ा कुप्रथा है। क्योंकि कम उम्र में बच्चों की शादी कर देने से उनके स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक विकास के साथ-साथ उनके खुशहाल जीवन पर असर पड़ता है। साथ ही वह अपने शिक्षा और खेलकूद के अधिकारों आदि से वंचित रह जाते हैं। इस कुप्रथा का शिकार ज्यादातर कम उम्र की लड़कियां होती है। बाल्यकाल में विवाह होने से बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास नहीं हो पाता है।

विकास के दौर में बाल विवाह एक नासूर के समान है। देश में हर व्यक्ति को शिक्षित करने की मुहिम चल रही है। हर व्यक्ति को उत्तम स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में बाल विवाह होना समाज के माथे पर एक कलंक के समान है। देश में अक्षय तृतीया (आखा तीज) पर हर वर्ष हजारों की संख्या में बाल विवाह किए जाते हैं। तमाम प्रयासों के बावजूद हमारे देश में बाल विवाह जैसी कुप्रथा का अन्त नही हो पा रहा है। भारत में बेटी-बचाओ-बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान के शुरू होने के बावजूद एक नाबालिग बेटी की जबर्दस्ती शादी करा दी जा रही है। बाल विवाह मनुष्य जाति के लिए एक अभिशाप है। यह जीवन का एक कड़वा सच है कि आज भी छोटे-छोटे बच्चे इस प्रथा की भेंट चढ़े जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर जगह बेटी बचावो बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। देश के सभी प्रदेशों में बेटियां शि्षा कृत हो रही है। ऐसे में समाज को आगे आकर कम उम्र में लड़कियों के होने वाले बाल विवाह रुकवाने के प्रयास करने होंगे। आजकल कई लड़कियां खुद भी आगे आकर

मैं बांधकर क्यों उनका जीवन बर्बाद कर दिया जाता है। देश में बाल विवाह के 50 प्रतिशत से अधिक मामले केवल 5 राज्यों से संबंधित हैं जिनमें उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। शेष चार राज्यों में बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश शामिल हैं। वर्तमान में भारत में बाल विवाह के लगभग 22 प्रतिशत मामले हैं जो कि लगातार कम हो रहे हैं। इसके प्रमुख कारणों में महिलाओं में साक्षरता और जागरूकता का बढ़ना, शिक्षा के प्रसार के कारण लड़कियों के प्रति अभिभावकों की सोच में परिवर्तन आना, शहरीकरण में वृद्धि तथा कठोर कानूनों की उपस्थिति को माना जा सकता है।

भारत में बाल विवाह में गिरावट आई है। लेकिन देश में पांच लड़कियों में से एक और छह लड़कों में से एक की अभी भी बचपन में शादी कर दी जाती है। हाल के वर्षों में यह प्रथा कुछ राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में अधिक प्रचलित हो गई है। दिसंबर 2023 में द लैंसेट ग्लोबल हेल्थ में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार यह अनुमान लगाने वाले पहले अध्ययनों में से एक है कि राज्य व केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर समय के साथ लड़की और लड़के के बाल विवाह की दर में क बदलाव आया है। अध्ययन में पाया गया कि 1993 से 2021 के बीच राष्ट्रीय स्तर पर बाल विवाह में गिरावट आई है। बालिका बाल विवाह का प्रचलन 1993 में 49 प्रतिशत से घटकर 2021 में 22 प्रतिशत हो गया। जबकि बालक बाल विवाह 2006 में 7 प्रतिशत से घटकर 2021 में 2 प्रतिशत हो गया। बाल विवाह के प्रचलन में सबसे बड़ी कमी 2006 और 2016 के बीच हुई। सबसे कम कमी 2016 से 2021 के बीच

भारत में यह प्रथा लम्बे समय से चली आ रही है जिसके तहत छोटे बच्चों का विवाह कर दिया जाता है। आश्चर्य की बात तो यह है कि आज के पढ़े लिखे समाज में भी यह प्रथा अपना स्थान बनाए हुए है। जो बच्चे अभी खुद को भी अच्छे से नहीं समझते। जिन्हें जिन्दगी की कड़वी सच्चाईयों का कोई ज्ञान नहीं। जिनकी उम्र अभी पढ़ने लिखने की होती है। उन्हे बाल विवाह के बंधन में बांधकर क्यों उनका जीवन बर्बाद कर दिया जाता है।

बाल विवाह के खिलाफ जोरदार अभियान की आवश्यकता

हुई। इन बाद के वर्षों के दौरान छह राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में बालिका विवाह में वृद्धि देखी गई। आंकड़ों से साफ है कि आजादी के 77 साल बाद भी इस देश में महिलाओं की स्थिति में कोई खास सुधार नहीं आया है। हम अपनी बेटियों को बाल विवाह और कम उम्र की गर्भावस्था से नहीं बचा पाए हैं। यही कारण है कि इस देश में 50 फीसदी से ज्यादा महिलाएं और बच्चे एनीमिया (रक्ताल्पता) के शिकार हैं। यूनिसेफ द्वारा जारी की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत के कई क्षेत्रों में अब भी बाल विवाह हो रहा है। इसमें कहा गया है कि पिछले कुछ दशकों के दौरान भारत में बाल विवाह की दर में कमी आई है। लेकिन कई प्रदेशों में यह प्रथा अब भी जारी है। रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह की यह कुप्रथा आदिवासी समुदायों सहित कुछ विशेष जातियों के बीच प्रचलित है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बालिका शिक्षा की दर में सुधार, किशोरियों के कल्याण के लिये सरकार द्वारा किये गए निवेश व कल्याणकारी कार्यक्रम और इस कुप्रथा के खिलाफ सार्वजनिक रूप से प्रभावी संदेश देने जैसे कदमों के चलते बाल विवाह की दर में कमी देखने को मिली है। यूनिसेफ के अनुसार अन्य सभी राज्यों में बाल विवाह की दर में गिरावट लाए जाने की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। किंतु कुछ जिलों में बाल विवाह का प्रचलन अब भी उच्च स्तर पर बना हुआ है। यह रिपोर्ट हमारे सामाजिक जीवन के उस स्याह पहलू कि ओर इशारा करती हैं। जिसे अक्सर हम रीति-रिवाज व परम्परा के नाम पर अनदेखा करते हैं। देश में बाल विवाह के खिलाफ चलाने होंगे ताकि गरीब परिवार गरीब परिवारों की बच्चियां कानून बने हैं और समय-समय पर उसमें संशोधन कर उसे बाल विवाह का निशाना न बन पाएं।

भारत में गरीबी उन्मूलन पर पूर्व में गम्भीरता से ध्यान ही नहीं दिया

भारत में हाल ही के वर्षों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिकों की संख्या में आई भारी कमी के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक एवं विकसित देशों के कई वित्तीय एवं आर्थिक संस्थानों ने भारत की आर्थिक नीतियों की मुक्त कंठ से सराहना की है। यह सब दरअसल भारत में तेज गति से हुए वित्तीय समावेशन के चलते सम्भव हुआ है। याद करें वर्ष 1947, जब देश ने राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त की थी, उस समय देश की अधि कतम आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर थी। जबकि, भारत का इतिहास वैभवशाली रहा है एवं भारत को ह्दसोने की चिड़ियाहण कहा जाता था। परंतु, पहिले अरब से आक्रांताओं एवं बाद में अंग्रेजों ने भारत को जमकर लूटा तथा देश के नागरिकों को गरीबी की ओर धकेल दिया। भारत में राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत से ह्दगरीबी हटाओह्ण के नारे तो बहुत लगे परंतु, गरीबी नहीं हटी। ह्दगरीबी हटाओह्ण के नारे के साथ राजनैतिक दलों ने कई बार सता हासिल की किंतु देश से गरीबी हटाने के गम्भीर प्रयास शायद कभी नहीं हुए और गरीब वर्ग को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा।

भारत में प्रधानमंत्री जनधन योजना को वर्ष 2014 में लागू किया गया जिसके माध्यम से आम नागरिकों के बैंकों में बचत खाते खोले गए, आवश्यकता आध रित ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित की गई, धन के प्रेषण की सुविधा, बीमा तथा पेंशन सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। इस योजना के अंतर्गत जमाराशि पर ब्याज मिलता है, हालांकि बचत खाते में कोई न्यूनतम राशि रखना आवश्यक नहीं है। एक लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा भी मिलता है। साथ ही, इस योजना के माध्यम से दो लाख रुपए का जीवन बीमा उस लाभार्थी को उसकी मृत्यु पर सामान्य शर्तों पर मिलता है।

भारत में प्रधानमंत्री जनधन योजना को सफलता पूर्वक लागू करने के बाद प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना को भी लागू किया गया जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार एवं विभिन्न राज्य सरकाराें द्वारा गरीब वर्ग के हितार्थ चलाई जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सहायता की राशि को सीधे ही हितग्राहियों के बचत खातों में जमा कर दिया जाता है। इससे विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को 100 प्रतिशत लाभ की राशि सीधे ही उनके हाथों में पहुंच जाती है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के अंतर्गत, वर्ष 2013 के बाद से 31 मार्च 2022 तक, 24.8 लाख करोड़ रुपए की राशि सीधे ही लाभार्थियों के बचत खातों में जमा की जा चुकी है, इसमें अकेले वित्तीय वर्ष 2021-22 में ही 6.3 लाख करोड़ रुपए की राशि लाभार्थियों के बचत खातों में हस्तांतरित की गई थी। वर्ष 2014 के पूर्व तक जब इन लाभार्थियों के बचत खाते विभिन्न बैंकों में नहीं खुले थे तब तक कांग्रेस एवं अन्य सरकारों के शासनकाल के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सहायता की राशि सामान्यतः नकद राशि के रूप में इन लाभार्थियों को उपलब्ध कराई जाती थी। आपको शायद ध्यान होगा कि एक बार देश के प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी ने कहा था कि केंद्र सरकार से विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सहायता की राशि के एक रुपए में से केवल 16 पैसे ही लाभार्थियों तक पहुंच पाते हैं। शेष 84 पैसे इन योजनाओं को चलाने वाले तंत्र की जेब में पहुंच जाते है। अब आप स्वयं आंकलन करें



आजादी के लगभग 70 वर्षों के बाद भी भारत के 50 प्रतिशत नागरिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ अर्थात बैंकों से नहीं जुड़े थे। प्रध नमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खाताधारकों को प्रदान की जाने वाली अन्य सुविधाओं का लाभ भी भारी मात्रा में नागरिकों ने उठाया है।

कि यदि बैंक में 50 करोड़ लाभार्थियों के बचत खाते नहीं खुले होते और यदि उक्त वर्णित केवल 8 वर्षों के दौरान उपलब्ध कराई गई 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न लाभार्थियों को नकद राशि के रूप में उपलब्ध कराई जाती तो इन लाभार्थियों के पास केवल 4 लाख करोड़ रुपए की राशि ही पहुंच पाती एवं शेष 21 लाख करोड़ रुपए की राशि इन योजनाओं को चलाने वाले तंत्र के पास ही रह जाती। अब आप आगे एक और कल्पना कर लीजिये कि पिछले 70 वर्षों के दौरान कितनी भारी भरकम राशि इन गरीब हितग्राहियों तक नहीं पहुंच पाई होगी। इस राशि का आकार शायद आपकी कल्पना से भी परे है। सहायता की यह राशि यदि गरीबों तक पहुंच गई होती तो शायद हो सकता है कि देश से अभी तक गरीबी भी दूर हो चुकी होती। अब जब प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के अंतर्गत सहायता की राशि हितग्राहियों के खातों में सीधे ही पहुंच रही है तो देश से गरीबी भी तेजी से कम होती दिखाई दे रही है, जिसकी तारीफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुक्त कंठ से हो रही है। पिछले 10 वर्षों के दौरान केंद्र सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय बैंकों के माध्यम से इस दृष्टि से बहुत ठोस कार्य किया गया है। न केवल 50 करोड़ से अधिक बचत खाते विभिन्न भारतीय बैंकों में खोले गए हैं बल्कि आज इन बचत खातों में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि भी जमा हो गई है और बचत की यह भारी भरकम राशि बैंकों द्वारा देश के आर्थिक विकास में उपयोग की जा रही है। इस प्रकार, भारत का गरीब वर्ग भी इन बैंक खातों के माध्यम से देश के आर्थिक विकास में प्रत्यक्ष रूप से अपना योगदान देता हुआ दिखाई दे रहा है। उक्त 50 करोड़ से अधिक बचत खातों में 50 प्रतिशत खाते महिलाओं द्वारा खोले गए हैं, अर्थात अब

भारतीय महिलाएं, ग्रामीण महिलाओं सहित, भी आत्मनिर्भर बनती जा रही हैं। भारी मात्रा में खोले गए इन बचत खातों के माध्यम से गरीब वर्ग के नागरिकों का बैंकिंग सम्बंधी इतिहास भी धीरे धीरे विकसित हो रहा है, जिससे इस वर्ग के नागरिकों को बैंकों द्वारा ऋण प्रदान करने में आसानी होने लगी है। केंद्र सरकार द्वारा बैंकों के माध्यम से लागू की जा रही विभिन्न प्रकार की ऋण योजनाओं का लाभ भी अब गरीब वर्ग को मिलने लगा है। कोरोना मह. त्मारी के तुरंत बाद जब देश में स्थितियां सामान्य बनने की ओर अग्रसर हो रहीं थीं तब केंद्र सरकार ने खोमचा वाले, रेहड़ी वाले एवं ठेलों पर अपना सामान बेचकर छोटे छोटे व्यवसाइयों द्वारा अपना व्यापार पुनः प्रारम्भ करने के उद्देश्य से एक विशेष ऋण योजना प्रारम्भ की थी। इस योजना के अंतर्गत उक्त वर्णित छोटे छोटे व्यवसाइयों को बैंक द्वारा आसानी से ऋण प्रदान किया गया था क्योंकि इस वर्ग के नागरिकों के पूर्व में ही बैंकों में बचत खाते खुले हुए थे। बैंकों द्वारा यह ऋण बगैर किसी व्यक्तिगत गारंटी के प्रदान किया गया था। और, हजारों की संख्या में छोटे छोटे व्यवसाइयों ने निर्धारित समय सीमा में इस ऋण को अदा कर, पुनः बड़ी हुई राशि के ऋण बैंकों से लिए थे और अपने व्यवसाय को तेजी से आगे बढ़ाया था। बैंकों में खोले गए बचत खातों से गरीब वर्ग को इस प्रकार के लाभ भी हुए हैं।

भारत में प्रधानमंत्री जनधन योजना ने देश के हर गरीब नागरिक को वित्तीय मु ख्य धारा से जोड़ा है। समाज के अंतिम छोर पर बैठे गरीबतम व्यक्तियों को भी इस योजना का लाभ मिला है। आजादी के लगभग 70 वर्षों के बाद भी भारत के 50 प्रतिशत नागरिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ अर्थात बैंकों से नहीं जुड़े थे। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खाताधारकों को प्रदान की जाने वाली अन्य सुविधाओं का लाभ भी भारी मात्रा में नागरिकों ने उठाया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से 15.99 करोड़ नागरिक जुड़ गए हैं, इनमें 49 प्रतिशत महिलाएं शामिल हैं, इस योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए का जीवन बीमा केवल 436 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर उपलब्ध कराया जाता है। प्रध नमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से 33.78 करोड़ नागरिक जुड़ गए हैं, इनमें 48 प्रतिशत महिला लाभार्थी हैं, इस योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा केवल 20 रुपए के वार्षिक प्रीमीयम पर उपलब्ध कराया जाता है। अटल पेंशन योजना से 5.20 करोड़ नागरिक जुड़ गए हैं। मुद्रा योजना के अंतर्गत 40. 83 करोड़ नागरिकों को ऋण प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना अपने प्रारम्भिक समय से ही वित्तीय समावेशन के लिए एक क्रांतिकारी कदम मानी जा रही है। इस योजना के अंतर्गत खोले गए बचत खातों में से लगभग 67 प्रतिशत बचत खाते ग्रामीण एवं अर्धशहरी केंद्रों पर खोले गए हैं, जिसे मजबूत होती ग्रामीण अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जा रहा है। भारत में बैंकिंग व्यवस्था को आसान बनाने के उद्देश्य से डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाने का कार्य भी सफलतापूर्वक किया गया है। इस योजना के अंतर्गत खोले गए बचत खाताधारकों को रूपे डेबिट कार्ड प्रदान किया गया है। यह रूपे कार्ड उपयोगकर्ता द्वारा समस्त एटीएम, पोस टर्मिनल एवं ई-कामर्स वेबसाइट पर लेनदेन करने की दृष्टि से उपयोग किया जा सकता है। वर्ष 2016 में 15.78 करोड़ बचत खाताधारकों को रूपे कार्ड प्रदान किया गया था एवं अप्रैल 2023 तक यह संख्या बचकर 33.5 करोड़ तक पहुंच गई है।



जनता का विश्वास बनी मोदी-योगी की जोड़ी

सियासी गलियारे में वैसे भी यह कहावत पुरानी है कि इस बार 2014 और दिल्ली के सिंहासन का रास्ता यूपी से होकर गुजरता 2019 का रिकॉर्ड टूटेगा है। यानी जिस पार्टी के पास यूपी में सबसे अधिक सीटें और यूपी इतिहास होंगी, प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने का उसका रास्ता रचेगा।' यूपी के चुनावी उतना ही आसान होगा। यही वजह है कि यूपी की 80 सफर में 2014 का सीटों पर जीत हासिल करने के लिए राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव मील 2024 लोकसभा चुनावों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। का पत्थर साबित हुआ। अलबत्ता सियासी पैतरेबाजी से उलट राजनीतिक इसी साल यूपी में विश्लेषक यही मान रहे हैं कि इस बार यूपी में लोकसभा भाजपा का सियासी चुनाव के परिणाम अप्रत्याशित नहीं होंगे। भाजपा 2019 वनवास पूरा हुआ। उस लोकसभा चुनावों का प्रदर्शन बखूबी दोहराएगी। मोदी समय भाजपा के सामने और योगी की जोड़ी एक बार फिर करिश्माई प्रदर्शन कोई गठबंधन नहीं था। करेगी। दरअसल, मोदी-योगी की जोड़ी जीत की गारंटी भाजपा ने करीब 43 फीसदी वोट हासिल करते हुए 80 में तरह रुक गया। यूपी में भाजपा का वोट प्रतिशत भी 2014 बन चुकी है, जिसके आगे विपक्षी तेवर भी ढीले नजर से 71 सीटों पर जीत दर्ज की थी। समाजवादी पार्टी ने आते हैं। विपक्ष के पास इस जोड़ी की कोई काट नहीं। पांच सीटें जीती। जबकि, कांग्रेस मात्र 2 सीटों पर ही विगत दो लोकसभा चुनावों के मुकाबले 2024 चुनाव में भाजपा अगर यूपी में लोकसभा की सभी 80 सीटों पर सिमटकर रह गई थी। बसपा का तो खाता भी नहीं खुला स्थिति बिल्कुल अलग है। सपा ने इस बार कांग्रेस से हाथ जीत के लक्ष्य के साथ चुनावी मैदान में ताल ठोंक रही है, था। 2019 लोकसभा चुनाव में मोदी लहर और योगी कायों के दम पर बीजेपी ने चुनावी दंगल में पुनः ताल कई बार सार्वजनिक मंचों से योगी के विकास मॉडल की टोंकी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो साल का कार्यकाल तारीफ कर चुके हैं। प्रधानमंत्री इसी मॉडल के जरिए यूपी पूरा कर चुके थे। नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए समाजवादी और सुभासपा जैसे क्षेत्रीय दलों के साथ भी गठबंधन किया की सभी सीटों पर जीत का दावा भी कर रहे हैं। जैसा कि पार्टी और बसपा साथ आए। रालोद ने भी साथ दिया। है। भाजपा इस लोकसभा चुनाव में यूपी में बेहतर स्थिति अमररोहा की अपनी चुनावी जनसभा में प्रधानमंत्री ने कहा हालांकि चुनाव परिणाम पुनः भाजपा के पक्ष में ही रहा। में है तो इसमें केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियों के भी कि 'लिखकर ले लीजिए। सात साल से यूपी में योगी भाजपा ने करीब 50 फीसदी वोट शेयर के साथ 61 सीट साथ योगी मॉडल का अहम योगदान है। केंद्र में जिस तरह की सरकार है। 2019 लोकसभा चुनाव के समय उन्हें दो जीती। बसपा 10 सीट, सपा 5 सीट और कांग्रेस के खाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजनाओं को जमीनी स्तर पर ही साल काम करने का मौका मिला था। अब तो सात में महज एक सीट आई। योगी ने 2019 के बाद एक उतारा। जिस तरह गरीब, युवा, महिला और किसानों के जीवन में खुशहाली लेकर आए उसी तरह योगी ने यूपी में के गंध में है लेकिन इतना तय है कि मोदी-योगी की होता है। कानून व्यवस्था क्या होती है। विकास क्या होता बनाई और जिसकी परिणिति उत्तरप्रदेश में बुलडोजर सुशासन का राज कायम काम किया। योगी के सुशासन को जोड़ी पर यूपी की जनता का विश्वास बना हुआ दिख रहा है और इसलिए योगी के नेतृत्व में इस बार रिकॉर्ड टूटेगा। के रूप में सामने आई। जो कहीं न कहीं 2022 विध



लसभा चुनाव में भाजपा होती है कि सात साल के कार्यकाल में एक भी दंगे नहीं का चुनावी सिंबल सा बन हुए। जबकि पहले के मुख्यमंत्रियों के समय औसतन हर गया। मुख्यमंत्री ने राज्य में तीसरे-चौथे दिन एक दंगा होता था। यह किसी से छिपा कानून व्यवस्था के मोर्चे नहीं है कि पहले पेशेवर माफिया और अपराधी सत्ता के पर अपने प्रदर्शन के चलते संरक्षण में दहशत फैलाते थे। चुनाव को आभासी जनमत योगी राज में माफियाओं पर लगाम लगी। यूपी में जनता संग्रह बना दिया था। अब भयमुक्त है, अपराधियों के मन में कानून का खौफ है। भाजपा ने चुनावों पुलिस अपराधियों, माफियों और दंगाइयों पर कहर बनकर में ऐतिहासिक वापसी की टूटी है। उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त, भयमुक्त एवं दंगामुक्त और तीन दशकों से चल हुआ है। प्रदेश में पुलिस के डर से बड़े-बड़े अपराधी और रहा समाजवादी पार्टी की माफिया प्रदेश छोड़कर या तो भाग गए या उन्होंने आत्म. साइकिल का पहिया पूरी समर्पण कर दिए हैं। यूपी में विकास योजनाओं को अमलीजामा पहनाने में केंद्र सरकार ने भी भरपूर साथ दिया। यही वजह है कि केंद्र की योजनाओं यूपी में खूब फलीभूत हुई। जिस कारण यूपी की अर्थव्यवस्था में गुणात्मक सुधार हुए। वर्ष 2016-17 के मुकाबले राज्य का सकल घरेलू उत्पाद(जीएसडीपी) दोगुनी होकर 25 लाख करोड़ तक पहुंच गया। राज्य सरकार ने 2027 तक प्रदेश की अर्थ व्यवस्था को वन ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश का बजट 2016-17 में जहां 3.46 लाख करोड़ रुपये का था वहीं 2024-25 में यह दोगुने से भी अधिक 7.36 लाख करोड़ रुपये का हो गया। विकास के इन्हीं आंकड़ों की बदौलत भाजपा यूपी में मिशन 80 का लक्ष्य हासिल करने का दावा कर रही है। लोकसभा चुनावों में कौन बाजी मारेगा यह तो भविष्य के गंध में है लेकिन इतना तय है कि मोदी-योगी की जोड़ी पर यूपी की जनता का विश्वास बना हुआ दिख रहा है।

उच्च शिक्षित युवाओं की चौपाल थी, सो इसकी तो शुरुआत शिक्षा और बेरोजगारी की चर्चा से हुई पर वहीं तक नहीं ठहरी। जातिवाद, परिवारवाद और सामाजिक न्याय को लेकर बहस तक भी पहुंची। छात्राओं ने महिला सुरक्षा और महिला शिक्षा को चर्चा और बहस का मुद्दा बनाया, उसे सरकार की प्राथमिकता बताया तो छात्रों ने राष्ट्रवाद, परिवारवाद और जातिवाद से अपनी बात को आगे बढ़ाया। जैसे ही चर्चा में शामिल युवाओं की ओर से चुनावी माहौल में उनकी भूमिका का सवाल उछाला गया, जयकेश यादव ने शिक्षा और बेरोजगारी को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दा मानते हुए युवाओं का इसे लेकर रुझान बताया। मनीष चौहान ने इस क्रम को आगे बढ़ाया। हर नौजवान को किसी न किसी रोजगार से जोड़ने का मुद्दा उठाया। मनीष अभी अपनी बात रख ही रहे थे कि नितेश कुमार ने बहुजन समाज की ओर से चर्चा का रुख मोड़ा। बोले, सरकार वही चाहिए, जो बिना भेदभाव के बहुजन को नौकरी दे। दलितों का हित सबसे पहले सोचे। शिक्षा और रोजगार के इर्दगिर्द ही घुम रही चर्चा को हर्षवर्धन सिंह ने व्यापक रूप दिया है उन्होंने इससे राष्ट्रीय मुद्दों को जोड़ा और बोले हमें तो सबसे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा चाहिए नक्सलवाद से मुक्ति चाहिए पिछली सरकार ने यह करके दिखाया	शिक्षित युवाओं की लगी चौपाल	और अनुच्छेद 370 समाप्त करके देश में एक संविधान एक विधान और एक निशान को चलता किया एक युवा ने जब यह कहकर टोका कि हमें तो नौकरी चाहिए तो हर्षवर्धन ने 2017 से अब तक 6.5 लाख नियुक्तियों का आंकड़ा गिरना करोड़ ने शांत करने की कोशिश की हालांकि पूरी तरह वह सफल नहीं हो सके। उसके बाद राकेश वर्मा की बात रखने के लिए खड़े हुए उन्होंने निष्पक्ष के बाद से चर्चा आगे बढ़ाई स्वयं के मूल्यांकन के आधार पर सरकार सुनने की राह सुझाई । शिक्षा को व्यवस्था की बुनियाद बताते हुए उन्होंने कहा कि युवा सभी दलों के घोषणा पत्र में शिक्षा और रोजगार को खोजें और उसे आधार पर मतदान का निर्णय ले साथियों की बात ध्यान से सुन रही प्रकृति से जब उनका विचार पूछा गया तब वह बोली कि हमारा एक निर्णय 5 साल का दर्द हुआ देगा इसलिए मतदान देने से पहले सोच को एकांगी रखना खतरनाक हो सकता है। उन्होंने रोजगार को केवल नौकरी तस्वीर में इतना रखने की बात कही। उसमें स्वरोजगार को भी जोड़ने की सलाह दी। प्रकृति की बात को संघ्या ने लड़ते हुए मुद्दों की ओर खींचा इसे लेकर डूब जाता है या की इस बार के चुनाव में मुद्दे गायब है और धर्म और जाति के नाम पर वोटों की गणित बैठाई जा रही है।
---	---	--

चुनाव में मतदाताओं की उदासीनता

देश में मतदाताओं को लुभाने के लिए 73 प्रतिशत मतदान हुआ है। यह आकड़ा बाद में राजनीतिक दलों के साथ ही निर्वाचन आयोग भी बढ़ भी सकता है। फिलहाल आज चुनाव अयोग तमाम कवायदें करता आया है। इसके बावजूद के आंकड़े के अनुसार आंध्र प्रदेश में 68.12 मतदाताओं की उदासीनता से यही लगता है प्रतिशत, बिहार में 55.78 प्रतिशत, जम्मू-कश्मीर में 36.58 प्रतिशत, झारखंड में 63.37 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 68.44 प्रतिशत महाराष्ट्र में 52.63 मतदाताओं को बूथ तक लाने के लिए चुनाव के प्रतिशत, उड़ीसा में 63.85 प्रतिशत, तेलंगाना में 61.23 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 57.63 प्रतिशत उदासीनता का ही कारण है कि जिन्हें सभी और पश्चिम बंगाल में 75.91 प्रतिशत मतदान प्रत्याशियों से अधिक वोट मिलता है वह जीत हुआ है। जाते हैं और जिन्हें अधिक सीटें आती हैं वह तेलंगाना की सभी 17 लोकसभा सीट, आन्ध्र सरकार बना लेते हैं भले ही उन्हें आधे से अधि प्रदेश की 25, उत्तर प्रदेश की 13, बिहार की क फीसदी मत हासिल नहीं हुए हों। निर्वाचन पांच, झारखंड की चार, मध्य प्रदेश की आठ, आयोग के लिए जहां कम मतदान एक चुनौती है महाराष्ट्र की 11, ओडिशा की चार, पश्चिम बंगाल की आठ और जम्मू-कश्मीर की एक सीट वहीं राजनीतिक दलों के लिए भी चिंता का मुद्दा बना हुआ है। यहां यह उल्लेखनीय है कि विषय है कि मतदाता मतदान केन्द्रों। तक क्यों पर मतदान हुआ है। यहां यह उल्लेखनीय है कि नहीं आ रहा है। लोकतंत्र के प्रति जनता और जिस अनुच्छेद 370 को हटाना भारतीय. जनता मतदाताओं की प्राथमिकता न होना यह नहीं कहा पार्टी का उसके पूर्व संस्करण जनसंघ के दौर से जा सकता है कि वह जागरूक है क्योंकि वही मुद्दा बना हुआ था कि वह सत्ता में आने पर हटा मुद्दा बाहर आता है और कभी उत्सुक नहीं रहती है तीनों लोकसभा सीटों, श्रीनगर, बारामूला और तो कहीं न कहीं राजनीतिक दलों के मुद्दों और अर्न्तनाग-राजौरी में अपने प्रत्याशी तक नहीं उतारे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की दोनों पार्टियों नेशनल पालिकाओं के चुनाव में मतदान प्रतिशत के 10 एवं केंद्र शासित प्रदेशों की 96 संसदीय सीटों आमने-सामने लड़ रही हैं क्योंकि इनके बीच आंकड़ों से इसे आसानी से समझा जा सकता है पर मतदान सम्पन्न हो गया। अभी तीन चरण शेष गुप्तकार मीटिंग के बाद भी अभी तक इस प्रश्न महत्वपूर्ण इकाई राजनीतिक दल हमारे जीवन के हैं। चुनाव आयोग के अनुसार चौथे चरण में 62. पर कोई एका नहीं हो पाया है। लोकसभा चुनाव कितने पास और कितने दूर?

ताकि पक्षियों को राहत मिल सके

गर्मी अब सितम ढाने लगी है और सूरज भी पिछले कई दिनों से आग उगल रहा है। बढ़ती गर्मी में मानव जाति के साथ-साथ पशु-पक्षियों को भी ठंडे पानी की आवश्यकता होती है। आम व्यक्ति जहां ठंडे पानी की व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन पशु-पक्षी ठंडे जल की तलाश में भटकते रहते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत विकास परिषद सेवार्थ शाखा द्वारा एक अपील शुरू की गई है। साथ ही जिला प्रशासन के सहयोग से जिले में पक्षियों को दाना-पानी उपलब्ध कराने के लिए लोगों से सहयोग की अपील की जाएगी। शाखा के अध्यक्ष चंद्रभूषण मित्तल एवं मीडिया प्रभारी मोहित गर्ग ने बताया कि गर्मी जैसे-जैसे बढ़ रही है, वैसे ही आम आदमी के साथ पशु-पक्षी भी परेशान हैं। ऐसे में हर व्यक्ति का यह दायित्व है कि वह पक्षियों के प्रति दया का भाव रखें और उनके लिए दाने-पानी का इंतजाम करें। पक्षियों के लिए दाना-पानी रखना पुण्य का काय है। कहा कि घर की छत के ऊपर अथवा खुले स्थानों पर पक्षियों के लिए पानी और दाना रखा जा सकता है, जिससे उनके प्राणों की रक्षा हो सके। क्योंकि पक्षियों को पानी के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे में लोगों की जिम्मेदारी है कि वे पक्षियों के लिए दाना व पानी की उचित व्यवस्था करें, ताकि खुले आसमान और धूप में विचरण करने वाले पंछियों को राहत मिल सके।



सिक्किम स्थापना दिवस समारोह



जयपुर। रजस्थान में गत दिनों गुरुवार को सिक्किम स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान राज्यपाल कलराज मिश्र ने सिक्किम के स्थानीय लोगों से संवाद किया और उन्होंने स्थापना दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर का यह प्रदेश प्राकृतिक दृष्टि से ही संपन्न नहीं बल्कि भारत की सनातन संस्कृति का भी संवाहक बना। उन्होंने सिक्किम राज्य के इतिहास और संस्कृति की चर्चा करते हुए कहा कि 16 मई को यह भारत का 22वां राज्य बना था।

जलवायु परिवर्तन का बीमारियों पर असर



जलवायु परिवर्तन के कारण गर्म हुआ मौसम रोग फैलाने वाले जीवों को ज्यादा आवास मुहैया कराने के साथ ही प्रजनन का लंबा समय भी मुहैया कराता है। ऐसे में यदि परजीवियों की ज्यादा पीढ़ियां होंगी तो और ज्यादा बीमारियां भी हो सकती हैं। हालांकि धरती को इंसानों के रहने लायक बनाने जरूरी नहीं कि सारी प्रक्रियाओं से केवल संक्रामक रोग बढ़ते ही हैं। आवास के खत्म होने या उनमें बदलाव से संक्रामक रोगों में कमी भी आती है।

पृथ्वी के गर्म होने से बीमारियों के बढ़ने का खतरा पृथ्वी जैसे-जैसे गर्म होती जा रही है उसका प्रभाव हमारे जलवायु परिवर्तन पर भी पड़ रहा है जिसके फलस्वरूप गर्म, सूखी, प्रदूषित पृथ्वी पर बीमारियां भी बढ़ रही हैं। इन बीमारियों का असर जगह के हिसाब से पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन का बीमारियों पर असर पूरी धरती पर एक जैसा नहीं है। उष्ण कटिबंधीय जलवायु में गर्म और नमी वाला मौसम डेंगू बुखार की वि. स्फोटक स्थिति पैदा कर रहा है। दूसरी तरफ अफ्रीका के सुखे क्षेत्र में आने वाले दशकों में मलेरिया के संक्रमण वाले इलाके सिमट सकते हैं। साइंस जर्नल में हाल ही में आयी रिसर्च रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन, बारिश, वाष्पीकरण और धरती में पानी के समाने जैसी जलीय प्रक्रियाओं के संबंध का एक मॉडल तैयार दिखाया गया है। इंसान ने पृथ्वी को गर्म, सूखा और प्रदूषित करके कई जीवों के रहने रहने लायक नहीं छोड़ा है। इसके नतीजे में कई संक्रामक बीमारियों का फैलाव बढ़ रहा है। गर्म और सूखी जलवायु में मच्छर जैसे जीव खूब पनपते हैं। दूसरी तरफ इनका आवास खत्म होने से बीमारी फैलाने वाले ये जीव इंसानी बस्तियों के करीब आ जाते हैं। जलवायु और पृथ्वी पर इंसानों का प्रभाव किस तरह की जटिल समस्याएं पैदा कर रहा है. कैसे कुछ बीमारियों को भरपूर विस्तार का मौका मिलने के साथ ही उनके फैलाव के तरीकों में बदलाव आ रहा है। जैव विविधता का नुकसान संक्रामक रोगों के विस्तार में वैज्ञानिकों की आशंका से ज्यादा बड़ी भूमिका निभा रहा है। श्नेचरश जर्नल में छपी रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार रिसर्चरों ने पहले से मौजूद रिसर्चों के तीन हजार आंकड़ों का विश्लेषण कर यह पता लगाने की कोशिश की है, कि जैव विविधता का नुकसान, जलवायु परिवर्तन, रासायनिक प्रदूषण, बसेरों का खत्म होना या बदलना और नई प्रजातियों का आना, इंसानों, जानवरों और वनस्पतियों को कैसे प्रभावित करते हैं।

रिसर्च के बाद वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जैव विविधता का नुकसान सबसे बड़ा कारक है। इसके बाद की बड़ी वजहें जलवायु परिवर्तन और नई प्रजातियों का उभरना है। परजीवी उन प्रजातियों को निशाना बनाते हैं जो भरपूर संख्या में हैं, और परपोषी के रूप में ज्यादा सुविधाजनक साबित होते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण गर्म हुआ मौसम रोग फैलाने वाले जीवों को ज्यादा आवास मुहैया कराने के साथ ही प्रजनन

का लंबा समय भी मुहैया कराता है। ऐसे में यदि परजीवियों की ज्यादा पीढ़ियां होंगी तो और ज्यादा बीमारियां भी हो सकती हैं। हालांकि धरती को इंसानों के रहने लायक बनाने जरूरी नहीं कि सारी प्रक्रियाओं से केवल संक्रामक रोग बढ़ते ही हैं। आवास के खत्म होने या उनमें बदलाव से संक्रामक रोगों में कमी भी आती है। शहरीकरण के साथ साफ-सफाई में सुधार, पानी की सप्लाई और सीवेज सिस्टम से संक्रामक रोगों में कमी भी आती है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि अफ्रीका में मलेरिया का मौसम पहले के अनुमानों की तुलना में चार महीने छोटा हो सकता लीड्स यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर और रिसर्च रिपोर्ट के मुख्य लेखक मार्क स्मिथ हालांकि सावधान करते हुए कहते हैं कि सारे नतीजे जरूरी नहीं कि अच्छी खबरें ही लाएं। मलेरिया के लिए उपयुक्त ठिकाने बदल सकते हैं और इथियोपिया के ऊंचे इलाके प्रभावित होने वाली नए जगहों में शामिल हो सकते हैं। इन इलाकों में रहने वाले लोग मलेरिया के सामने ज्यादा कमजोर होंगे क्योंकि अब तक उनका इससे सामना नहीं हुआ है। स्मिथ का कहना है कि मलेरिया के लिए जो जरूरत से ज्यादा कठिन परिस्थितियां होंगी वह इंसानों के लिए भी मुश्किल पैदा करेंगी। पानी की मौजूदगी का मसला बहुत गंभीर हो सकता है। जलवायु और संक्रामक रोगों के बीच संबंध का मतलब है कि क्लाइमेट मॉडलिंग बीमारियों की उभरने की भविष्यवाणी की जा सकती हैं। स्थानीय तापमान और बारिश का पूर्वानुमान पहले से ही डेंगू का अनुमान लगाने में इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि यह बहुत थोड़ा समय पहले ही होता है और इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। एक विकल्प है इंडियन ओशन बेसिन वाइड इंडेक्स यानी यह हिंद महासागर में समुद्र की सतह के तापमान में होने वाली गड़बड़ियों के क्षेत्रीय औसत को मापता है। जर्नल साइंस में छपी रिसर्च रिपोर्ट ने तीन दशकों में 46 देशों के डेंगू के आंकड़े को भी देखा है और आईओबीडब्ल्यू के आंकड़ों की उठापटक के साथ उत्तरी और दक्षिणी गोलार्द्ध में बीमारियों के संक्रमण में संबंध का पता लगाया है। यद्यपि आईओबीडब्ल्यू के भविष्य बताने की ताकत को अभी परखा नहीं गया है। हालांकि इस पर नजर रख कर अधिकारी सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा बनने वाली बीमारियों को फैलने से रोकने की बेहतर तैयारी कर सकते हैं।

महिलाओं के लिए उपयोगी लापता लेडीज

महिलाओ पर पुरुषो के अत्याचार का इतिहास सदियों पति के साथ चली जाती हैं। उसके बाद की कहानी इन पुराना है कबीलाई समाज से लेकर सामंती समाज र दो महिलाओं के संघर्ष की कहानी है। जो अंत में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेती हैं। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक तो यह है कि नवविवाहिताओं को इतना लंबा घूँघट निकालने के लिए मजबर न किया जाए। उनका सिर ढका हो पर चेहरा खुला ही। दूसरा सबक यह है कि ग्रामीण परिवेश में पाली-बढ़ी, अनपढ़ या कम पढ़ी-लिखी लड़कियों को विदा करते समय उनके घर वालों को उस लड़की के सप्पाल और मायके का पूरा नाम पता और फोन नंबर लिख कर देना चाहिए। जैसा प्रायः मेलों और पर्यटन स्थलो में जाते समय शहरी माता-पिता अपने बच्चों की जैब में नाम-पता लिख कर पची रखदेते हैं। अगर भीड में बच्चा खो भी जाए तो यह पची उसकी मददगार होती है।इस फिल्म का तीसरा संदेश यह है कि शहरी लड़कियों की तरह अब ग्रामीण लड़कियां भी पढ़ना और आगे बढ़ना चाहती है जबकि उनके मां-बाप इस मामले में उनको प्रोत्साहित नहीं करते और कम उम्र में ही अपनी लड़कियों का ब्याह कर देना चाहते है। ऐसा करने से उस लड़की की आकांक्षाओं पर कुठाराघात हो जाता है और उसका शेष जीवन हताशा में गुजरता हैं। आज के इंटरनेट और सोशल मीडिया के युग में शायद ही कोई गांव होगा जो इनके प्रभाव से अछूता हो। हर किस्म की जानकारी, युवक- युवतियों को स्मार्टफोन पर घर बैठे ही मिल रही है। जरूरी नहीं कि सारी जानकारी सही ही हो, इसलिए उसकी विश्वसनीयता जांचना-परखना जरूरी होता है। जानकारी सही है और ग्रामीण परिवेश में पल रही कोई भी युवती उसके आधार पर आगे पढ़ना और अपना कैरियर बनाना चाहती है तो उसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए । फिल्म में दिखाया है कि कैसे एक युवती को उसके ८ र वालों ने उसकी मर्जी के विरुद्ध उसकी शादी एक विपरीत परिस्थितियों से जुझते हुए अपने गंतव्य तक पहुंच गई। पर ऐसा जीवट और किस्मत हर किसी की नहीं होती।

सतहि सेई करो हित अपना

स्वामी विवेकानंद का वाक्य है- राम कई हो सकते हैं, पर सीता एक ही होती हैं। राम मत्स्य भी हो सकते हैं, कच्छप भी हो सकते हैं, नरसिंह भी हो सकते हैं, वामन भी हो सकते हैं, परशुराम भी हो सकते हैं। कृष्ण, बुद्ध, कल्कि भी हो सकते हैं। लेकिन, सीता एक ही हैं। वाल्मीकिजी ने बहुत स्पष्ट कही, प्सीतायाः चरितं महत् ए अर्थात मेरी रामकथा में किसी का चरित्र महत्पूर्ण है तो वह सीता का ही है। उघर, तुलसी दास ने सबसे पहले र्शसीता शब्द का प्रयोग मंगलाचरण में किया। प्सीतारामगुणग्रामपुण्यारण्य विहारिणी। वहां सीता-राम दोनों की कथा है। मंगलाचरण के बाद- स्वतंत्र रूप में सीता की वंदना तुलसी ने र्मानसर्ष में की है :

उद्भववस्थितिसंहारकारिणीम्।
क्लेशहारिणीम् ।
सर्वश्रेयस्करी सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्॥
कैसी है यह मां? संसार को प्रकट करने वाली, पैदा करने वाली, फिर पालन करने वाली। पालन करते-करते जो अनावश्यक वस्तु जुड़ जाती है, उसका संहार करने वाली। फिर उनका दूसरा लक्षण बताया र्कलेशहारिणीर्ष। क्लेश को हरने वाली। फिर तीसरी बात लिखी सर्व कल्याण करने वाली। सबका मंगल करने वाली। श्नतोऽहं रामवल्लभाम्॥ तुलसी कहते हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं, जो श्रीराम को अत्यंत प्रिय हैं। मां जन्म देती है, पालन करती है। खेलते-खेलते बच्चे के शरीर पर अनावश्यक गंदगी लग जाती है, तो उसको मिटाने वाली भी मां ही होती है। सीता जी में माता के ये तीनों लक्षण विद्यमान हैं। सीता तो जगदंबा हैं, आह्लादिनी शक्ति हैं परमात्मा की। दूसरी बात, सीता क्लेशहारिणी हैं। हमारे जीवन में क्लेश बहुत हैं। सांसारिक रूप में क्लेश कष्ट हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप में जो क्लेश हैं, पतंजलि ने योगसूत्र में उनकी चर्चा की है। क्लेश पांच हैं। एक है राग। दूसरा द्वेष।



बड़ा भारी चुनाव है
कहीं पर कोई अभिनेत्री से डर रहा कोई दो जगह से नामांकन भर रहा दिन रात एक कर रहा जीत के लिए भगवान से यही दुआ कर रहा कोई नहीं जानता वोटर का किधर झुकाव है लोग कहते हैं इस बार बड़ा भारी चुनाव है चार सौ पार का नारा कोई लगा रहा कोई एक को कोई दूसरे को चोर बता रहा अपने गिरेबान में कोई झांकता नहीं दूध का धुला खुद को दिखा रहा दल छोड़ने की होड़ है जिनका मन मुटाव है लोग कहते हैं इस बार बड़ा भारी चुनाव है लोगों को वायदों से हर दल लुभा रहा कड़वी जुबान के कोई तीर चला रहा खुद का भाषा पर नियंत्रण नहीं कोई दूसरों को मर्यादा में रहने का पाठ पढ़ा रहा सौहार्द के वातावरण को कर रहा खराब है लोग कहते हैं इस बार बड़ा भारी चुनाव है सत्ता प्राप्ति के लिए कोई कुछ भी कर रहा तानाशाही दिखाकर कानून से भी नहीं डर रहा महंगाई बेरोजगारी पर मन्दिर मस्जिद भारी है महंगाई से आम आदमी तिल तिल मर रहा लोगों को आपस में लड़ा रहा जनाब है लोग कहते हैं इस बार बड़ा भारी चुनाव है ए सी में बैठने वाले खूब पसीना बहा रहे करोड़ों की गाड़ियों में घूमने वाले पैदल आ जा रहे पसीने से जिसके कभी आती थी बदबू आज उसी को कस कर गले लगा रहे लोगों से सत्ता के लिए यह कैसा जुड़ाव है लोग कहते हैं इस बार बड़ा भारी चुनाव है

रवींद्र कुमार शर्मा
घुमारखी
जिला बिलासपुर हि प्र

तीसरा अविद्या। चौथा अस्मिता। अस्मिता वैसे तो प्यारा शब्द है, लेकिन यह मूलतः क्लेश है। अस्मिता का अर्थ होता है गौरव, लेकिन गौरव कब अहं में बदल जाए, कहना मुशिकल है। पांचवां क्लेश है जिजीविषा। मां सीता का स्मरण स्वाभाविक क्लेश को मिटाने वाला है। र्मानसर्ष में जो प्रधान पात्र हैं, उनका श्रेय (कल्याण) प्रत्यक्ष या परोक्ष सीता ने ही किया है। सबसे पहले सुग्रीव का श्रेय अर्थात कल्याण सीता ने किया है। सुग्रीव को देखकर रावण द्वारा अपहृत जानकी अपने वस्त्र, अलंकार सुग्रीव पर पफेंकती हैं। यह उनके श्रेय का श्रीगणेश है। रावण का श्रेय भी जानकी द्वारा ही हुआ। अंगद का श्रेय मां जानकी ने किया। हनुमानजी पर तोमा की कृपा बरस पड़ी है। संबसे बड़ाहनुमानजी का श्रेय यह किया कि तुम पर राम बहुत प्रेम करेंगे। सर्व का श्रेय करने वाली सीता जी हैं। औरों का श्रेय तो किया ही, रामजी का श्रेय सीता ने ही किया है। सती ने सीता का वेश लिया, तो आध्यात्मिक लाभ हो गया। खोखली बौद्धिकता समाप्त हो गई और श्रद्धा प्रकट हो गई। शरणागत श्रद्धा का जन्म हुआ तो यह श्रेय हुआ। सबसे पहले सग्रीव का श्रेय सीता जी ने किया। अपहृत जानकी ने अपने वस्त्र, अलंकार सुग्रीव पर फेंके, वहाँ से उसके कल्याण का आरंभ हुआ। सीता कहती हैं, मैंने पार्वती से प्रार्थना की तो उन्होंने मुझे केवल एक फूल की माला दी, लेकिन आज मैं सुग्रीव को मेरे महत्व के वस्त्र, अलंकार प्रसन्नता से डालती हूं । रावण सीता का भक्त बना, इसलिए उसका श्रेय हुआ।

एहि के हृदय बस जानकी
जानकी उर मम बास हैं।
मम उदर भुअन अनेक
लागत बान सब करे नास है॥
कुंभकर्ण का श्रेय भी सीता ने किया। कुम्भकरण ने सीता का ही स्मरण किया था।स्मरण मात्र से सीता जी ने ऐसे कुम्भकरण का श्रेय किया कि पता ही न लगे।





लोकसभा चुनाव-2024



बदलाव के दौर से गुजरती हरियाणा की राजनीति

भाजपा का लक्ष्य सभी सीटें जतना

2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा खट्टर को हरियाणा के राजनीतिक परिदृश्य में लाकर उन्हें राखी का मुख्यमंत्री बनाया गया था मोदी का विचार सिर्फ राज्य की राजनीति में जाटों के वर्चस्व को तोड़ना था। राज्य की राजनीति में कोई महत्वपूर्ण जाट नेता न होने के कारण मोदी अपने उद्देश्य में सफल रहे। हालांकि 2019 के राज्य चुनाव में, दुष्यंत चौटाला की जेजेपी जाट समर्थन आधार के साथ उभरी। यह भाजपा नेतृत्व के लिए एक झटका था क्योंकि पारटी ने कुछ महीने पहले ही राज्य को सभी 10 लोकसभा सीटें जीती थीं भाजपा की इतनी राजनीतिक किस्मत का गिरना अप्रत्याशित था और पार्टी को मुख्यमंत्री खट्टर के नेतृत्व में राज्य सरकार बनाने के लिए जेजेपी के साथ गठबंधन करना पड़ा। पांच साल बाद 2024 में, पीएम मोदी को लगा कि भाजपा अपनी लोकसभा सीटों को अपने सहयोगी जेजेपी के साथ साझा नहीं कर सकती है, और इसलिए जेजेपी को अप्रत्याशित था और पार्टी को मुख्यमंत्री खट्टर के नेतृत्व में राज्य सरकार बनाने के लिए जेजेपी के साथ गठबंधन करना पड़ा। पांच साल बाद 2024 में, पीएम मोदी को लगा कि भाजपा अपनी लोकसभा सीटों को अपने सहयोगी जेजेपी के साथ साझा नहीं कर सकती है, भाजपा नेतृत्व इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था कि राज्य में पंजाबी समुदाय मनोहर लाल खट्टर से खुश नहीं है, पहले हरियाणा की राजनीति में काफी बदलाव जो खुद एक पंजाबी है। उन्होंने राज्य में ओबीसी समुदाय को भी नाराज कर दिया था। ओबसी राजनीति की खोज में, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने खट्टर की जगह ओबीसी राजनेता सैनी को ले लिया है, हालांकि, ऐसा लगता है कि यह उल्टा हो गया है। पंजाबी और ओबीसी दोनों अब भाजपा नेतृत्व से इतने खुश नहीं हैं, क्योंकि दोनों समुदायों क कई लोग अपमानित महसूस कर रहे हैं और अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए तैयार हैं। समर्थन वापस लेने वाले तीन निर्दलीय विधायकों ने बताया है कि उन्होंने किसानों से जुड़े अन्य मुद्दों और युवाओं के बीच बढ़ती बेरोजगारी के अलावा अपने आत्मसम्मान के लिए ऐसा किया है। जहाँ तक जेजेपी का सवाल है, उसने राज्य की अल्पमत भाजपा सरकार को गिराने के

भाजपा जाहिर तौर पर अपनी सीटें बरकरार रखने में बहुत मुश्किल स्थिति में है, खासकर तब जब उसके साथ कोई सहयोगी नहीं है, पार्टी गुटबाजी में बंटी हुई है और उसका समर्थन आधार अब बिंखरता नजर आ रहा है। इस बार भाजपा के लिए अपनी खोई जमीन वापस पाना आसान नहीं होगा।

लिए प्रस्ताव लाने पर कांग्रेस को समर्थन देने की घोषणा की है। पांच साल बाद 2024 में, भाजपा को लगा कि वह अपनी लोकसभा सीटों को अपने सहयोगी जेजेपी के साथ साझा नहीं कर सकती है, और इसलिए जेजेपी को गठबंधन छोड़ने के लिए मजबूर करने के लिए अपमानित किया गया। मार्च में गठबंधन टूट गया। भाजपा नेतृत्व ने सोचा कि जेजेपी के अलग से चुनाव मैदान में होने पर भाजपा, इंडिया ब्लॉक और जेजेपी के बीच मुकाबला त्रिकोणीय हो जायेगा। 25 मई को छठे चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए 9 मई को नामांकन वापस लेने से रहे थे। जहाँ बहुत अधिक उत्साही लोग नहीं दिख रहे थे- न तो सड़क पर, न ही सड़क के किनारे दर्शक या घरों की छतों पर। सब कुछ सामान्य ही लग रहा था और, लोगों में चुनाव को लेकर कोई उत्साह नहीं दिख रहा था। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 58.21 फीसदी वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 28.51 फीसदी वोट मिले थे। हालांकि, कुछ ही महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और जेजेपी के साथ त्रिकोणीय मुकाबले में भाजपा सिर्फ 36.49 फीसदी वोट ही हासिल कर पायी। कांग्रेस को 28.08 फीसदी और जेजेपी को 14.80 फीसदी वोट मिले थे। भाजपा जाहिर तौर पर अपनी सीटें बरकरार रखने में बहुत मुश्किल स्थिति में है, खासकर तब जब उसके साथ कोई सहयोगी नहीं है, पार्टी गुटबाजी में बंटी हुई है और उसका समर्थन आधार अब बिंखरता

नजर आ रहा है। इस बार भाजपा के लिए अपनी खोई जमीन वापस पाना आसान नहीं होगा। 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा में भाजपा के पास केवल 40 विधायक हैं जबकि कांग्रेस के पास 30 और जेजेपी के पास 10 विधायक हैं दो सीटें खाली हैं क्योंकि खट्टर ने करनाल के विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था और रणजीत सिंह चौटाला ने रानिया से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में इस्तीफा दे दिया है। रणजीत हिसार लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार के रूप में भी चुनाव लड़ रहे हैं। इस प्रकार विधानसभा में प्रभावी सदस्य संख्या केवल 88 है। निर्दलीय विधायकों के जाने से सरकार अल्पमत में आ गई है। देखना यह है कि राज्य में भाजपा की अल्पमत सरकार रहते हुए लोकसभा चुनाव कराया जाता है या नई सरकार बनती है। इसके विपरीत कांग्रेस और आप ने लोकसभा चुनाव के लिए राज्य में हाथ मिलाया है। आप कुरूक्षेत्र से चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस बाकी 9 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जेजेपी और कांग्रेस ने अल्पमत भाजपा सरकार को हटाने के लिए राज्यपाल से मांग की है और अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस के पुनरुत्थान के साथ, इंडिया ब्लॉक भाजपा को चुनौती देने के लिए पूरी तरह तैयार है। फरवरी 2024 के हालिया किसान आंदोलन और खट्टर सरकार द्वारा उसके क्रूर दमन ने, पूरे किसान समुदाय को नाराज कर दिया है। उनका विरोध इतना था कि किसान आंदोलन शुरू होने के एक महीने के भीतर ही पीएम मोदी को खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटाना पड़ा। हालांकि खट्टर ने विश्वास जताया है कि 2024 के चुनावों में भाजपा फिर से सभी 10 लोकसभा सीटें जीतेगी, विश्लेषकों का मानना ​​है कि उन्हें खुद करनाल में कड़ी लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है, अपनी सीट बरकरार रखना भी बहुत मुश्किल है।

रामचरितमानस, पंचतंत्र मेमोरी आफ द वल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल नई दिल्ली। प्राचीन रामचरितमानस की सचित्र पांडुलिपियों और पंचतंत्र दंतकथाओं की 15वीं सदी की पांडलिपि को यूनेस्को के मेमोरी आफ द वल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि यह निर्णय सात-आठ मई को मंगोलिया की राजधानी उलानबटार हुई मेमोरी आफ द वल्ड कमिटी फार एशिया व एंड पैसिफिक (एमओडब्ल्यूसीएपी) की 10वी आम बैठक में लिया गया। तुलसीदास रचित रामचरितमानस की सचित्र पांडुलिपियां, सहृदयालोक की पांडुलिपि, पंचतंत्र दंतकथाओं की 15 वीं शताब्दी की पांडुलिपि को इस सूची में शामिल किया गया है। इस रजिस्टर में रामचरितमानस, सहृदयालोक, पंचतंत्र समेत एशिया प्रशांत क्षेत्र से कुल 20 दस्तावेज को शामिल किया गया है। दुनिया के महत्वपूर्ण दस्तावेज को संरक्षित करने और विशेषज्ञों को जानकारी उपलब्ध कराने के मकसद से मेमोरी आफ द वल्ड रीजनल रजिस्टर को बनाया गया है।



आस्तान-ए- शरीफ पर हुमा कुरैशी जयपुर। हुमा कुरैशी ने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अपनी हाजिरी के साथ चादरपोशी की।



घूँघट की बगावत (हिन्दी साप्ताहिक) द्वारा जनहित में जारी

प्रिय पाठकों, इस अंक में प्रकाशित सभी अग्रलेख, कथा-लघु कथा, कविता, व्यंग्य, विचार विमर्श लेखकों एवं विचारकों की अपनी कल्पना प्रसूति हैं। त्रुटियां मानवीय स्वभाव का अंग हैं जिनकी ओर ध्यान आकृष्ट करना एक जागरूक पाठक की विशेषता होती है। अतः आप सभी सुधी विज्ञजनों, से ऐसी अपेक्षा की जाती है कि आप अपने पत्रों के माध्यम से इस अंक में प्रकाशित त्रुटियों की ओर ध्यान आकृष्ट भी समय-समय पर कराते रहें ताकि उन त्रुटियों की पुनरावृत्ति से बचा जा सके। विवाद की स्थिति में न्यायालय, गोर खपुर का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।
—व्यवस्थापक

भारतीय राजनीति के कुछ मझे जालसाज

भारतीय राजनीति में कुछ इच्छाधारी नेता है, कुछ अवसरवादी राठी, योगेन्द्र यादव, संजय सिंह, अजित अंजुम जैसे कई नाम आंदोलनजीवी है, कुछ पिच मेकर है, कुछ ढोंगी है, कुछ है जो केवल राजनीतिक पिच बनाते है। योगेन्द्र यादव ने दावा दलबद्दल है और कुछ बहुरूपि है। जिस तरह डिबेटर किया है कि मीडिया वर्तमान में फ्रैक्ट दबा रही है। उनका के एक धड़े ने रेटिंग का चोला ओढ़ , ‘राजनीतिक विश्लेषक कहना है कि भाजपा को 2024 लोकसभा चुनावों में बहुमत के रूप में मोदी जी को बताया बहुमत से दूर वहीं पत्रकारों के नहीं मिलेगा। योगेन्द्र यादव ने कहा, 35 साल से चुनाव देखने भी एक धड़े ने चापलूसी का चोला ओढ़ विपक्ष के शान में के अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ कि भाजपा बहुमत कसीदे पड़े है। देश में लोकसभा चुनावों का माहौल है, लो. नहीं ला रही। भाजपा 272 से बहुत नीचे है। भाजपा सहयोगियों कतंत्र चुनावों की सरगर्मी चरम पर है। हर चुनाव की तरह खुद को राजनीतिक पंडित और चुनावी विशेषज्ञ बताने वाले पेशेवर प्रदर्शनकारी अपने - अपने मनघड़ंत अनुमानों के साथ वापस आ गए हैं। जिस तरह कोई भी उनके रवैये से इस बात का अंदाजा लगा सकता है, कुछ ने इस चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के बहुमत ना पाने की एक भविष्यवाणी कर दी तो कुछ अखिलेश को पीएम और राहुल को प्रेसिडेंट बनाने की बात कर सबका मनोरंजन कर रहा। ये कोई नयी बात नहीं है, ये फर्जी चुनाव विश्लेषक हर चुनाव के पहले आता है मोदी को हराता है, परिणाम पश्चात इनका मुंह काला होता है फिर ये बेशर्मी से टीवी पर बैठकर कहते है इवीएम हैक हो गई। अर्थात इन्होंने अपना काम कर दिया ,पिच बना दी,अब बल्लेबाज जैसे राहुल और अखिलेश ही रन ना बनाए तो ये पेडीए क्या करें। पीके, अरविन्द केजरीवाल, रविश कुमार, ध्रुव करके योगेन्द्र यादव ने समझाया कि भाजपा इस बार कम से

कम 75 सीट हारेगी और छक्का 100 सीट हारेगा। इसी हवा हवाई गणित के आधार पर योगेन्द्र यादव ने कहा कि भाजपा को 233 जबकि उनके सहयोगियों को 35 सीट मिलेगी। ऐसे में अंत में उन्होंने अपनी बात सिद्ध की कि भाजपा 272 के आँकड़े से नीचे रह जाएँगे। योगेन्द्र यादव ने यह पूरी गणित समझा दी लेकिन इसका स्रोत क्या है यह नहीं बताया। उनका कहना था कि मैं कहता हूँ तो मान ही लो। क्या पता सच ही हो जाए। साल के चार महीने प्रदर्शनों के लिए देने वाले योगेन्द्र यादव की इस गणित में ना किसी सर्वे का हवाला था और ना ही और कोई विश्वसनीय स्रोत। हालाँकि, यह कोई नई बात नहीं है कि योगेन्द्र यादव ऐसे बेसिर पैर के सर्वे देते हैं, इसे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में भी वह मुँह की खा चुके हैं। चाहे वह सीएए प्रदर्शन हो, किसानों का विरोध प्रदर्शन हो या कॉन्ग्रेस नेता राहुल गांधी की विवादास्पद भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होना हो, योगेन्द्र यादव हर उस काम में शामिल हैं, जो पीएम मोदी को सत्ता से हटाने के लिए हो रहा है। हालाँकि, उनके अब तक के प्रयासों से हार के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिला है यही आगे होने की संभावना है। हालांकि जब योगेन्द्र यादव का जब यह इंटरव्यू आया उस समय चार चरणों का चुनाव हो चुका है।

पंकज कुमार मिश्रा



स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक पंकजधर द्विवेदी द्वारा जनप्रकाशन प्रेस, निकट रीड्स साहब का धर्मशाला से मुद्रित एवं 45 बादशाहबाग, जगन्नाथपुर, गोरखपुर से प्रकाशित। सम्पादक—पंकज धर द्विवेदी सम्पर्क सूत्र— e-mail- ghoonghatkibagawat37@gmail.com

